● वर्ष-4
● अंक-85
रायपुर, रविवार
17 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» दोस्ती इतनी मजबूत हो कि लोग...

भाजपा-कांग्रेस की ओर से की गई शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त

दोनों दलों को पत्र लिखकर मांगा जवाब

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

दोनों राज्यों में राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। वहीं इस जुबानी जंग में आपत्तिजनक बयानों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इस पर चुनाव आयोग ने दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आयोग ने दोनों दलों को एक-दूसरे की शिकायत भेजीं हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत पर जवाब मांगा है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी भाजपा की ओर से की गई शिकायत का जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी

अध्यक्षों से 18 नवंबर को दोपहर एक बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई 2024 को जारी किए गए चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कराने के लिए कहा। इसमें स्टार प्रचारकों और नेताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया था। ताकि सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन न हो और चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा सके।

कांग्रेस ने यह आरोप लगाए थे

कांग्रेस ने 14 नवंबर को चुनाव अभियान के दौरान झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। विपक्षी दल ने आयोग से महाराष्ट्र और झारखंड में शेष चुनाव अभियान के लिए पीएम मोदी और शाह को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि से प्रतिबंधित करने, मामले की गहन जांच कराने की मांग की थी। कांग्रेस ने चुनाव अभियान के दौरान नफरती बयान देने वाले भाजपा में शामिल सभी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर को पीएम मोदी ने नासिक और महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। उन्होंने अपने बयानों में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर आरोप लगाए।

भाजपा ने की थी शिकायत

भाजपा ने 11 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत की थी। भाजपा ने कहा था कि राहुल गांधी ने राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाईं और झूठ बोला कि भाजपा संविधान को नष्ट करने वाली है। यह झूठ है। हमने आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग को यह भी बताया कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी हैं और चेतावनी और नोटिस के बाद भी वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

रिपोर्ट में हुए खुलासों से विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आया

जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदुओं का कराया जा रहा जबरन धर्म परिवर्तन?

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्वविद्यालय अक्सर विवादों में रहता है - कभी दीवाली के दिन हंगामा करने के संबंधित तो कभी राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित। अब एक रिपोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद को उजागर करने का दावा किया है, जो संस्थान में पढ़ने, पढ़ाने या काम करने वाले हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव और धमकियों के आरोपों पर केंद्रित है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जामिया के भीतर एक समूह मौजूद है जो हिंदुओं पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाता है और मना करने पर उन्हें बलात्कार या पढ़ाई में फेल करने जैसे परिणाम भुगतने की धमकी देता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट के बाद जांच के दायरे में आ गया है। जिसमें गैर-मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव और धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने के मामलों का आरोप लगाया गया है। एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस द्वारा तैयार की गई और प्रमुख कानूनी और प्रशासनिक हस्तियों के नेतृत्व

में तैयार की गई रिपोर्ट में संस्थान के भीतर पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने हिस्से के लिए कहा कि पिछले प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को गलत तरीके से संभाला हो सकता है, लेकिन वर्तमान प्रशासन एक समावेशी वातावरण बनाने पर केंद्रित था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने आरोपों को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने और किसी भी तरह के भेदभाव की निंदा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विश्वविद्यालय ने माना कि पिछले प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को गलत तरीके से संभाला होगा, लेकिन कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ के नेतृत्व में न्यायसंगत माहौल बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रशासन ने निर्णय लेने और प्रशासनिक भूमिकाओं में हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने की पहल पर प्रकाश डाला, जैसे कि गैर-मुस्लिम एससी समुदाय के सदस्यों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना। प्रो. आसिफ ने जाति, लिंग या धार्मिक भेदभाव के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई।

धर्म परिवर्तन के आरोपों का जवाब देते हुए, विश्वविद्यालय ने ऐसे दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत होने से साफ इनकार किया। विश्वविद्यालय ने इंडिया टुडे टीवी को बताया अगर कोई ठोस सबूत लेकर आता है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम शिकायतों के प्रति संवेदनशील हैं और एक सुरक्षित और समावेशी परिसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया

रिपोर्ट में गैर-मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव के विवरण सामने आए हैं। गवाहों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पूर्वाग्रह और पक्षपात के बारे में गवाही दी, जो कथित तौर पर विश्वविद्यालय के जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। अपमानजनक व्यवहार के उदाहरणों को उजागर किया गया, जिसमें एक सहायक प्रोफेसर को मुस्लिम सहकर्मियों से ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। एक अन्य घटना में पता चला कि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के एक गैर-मुस्लिम संकाय सदस्य के साथ असमान व्यवहार किया गया और उन्हें कार्यालय फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया., जो मुस्लिम समकक्षों को आसानी से प्रदान की जाती हैं। एक अन्य घटना में परीक्षा के सहायक नियंत्रक शामिल थे, जिनका स्टाफ के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपहास किया गया क्योंकि वे एक गैर-मुस्लिम थे और एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर थे। रिपोर्ट में आदिवासी छात्रों और शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के आरोपों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस विषाक्त वातावरण ने कथित तौर पर कई आदिवासी छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर किया। धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती के आरोप भी सामने आए हैं। एक मामले में, एक प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रों से कहा कि उनकी डिग्री पूरी करना इस्लाम धर्म अपनाने पर निर्भर है, उन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्तिगत लाभ का हवाला दिया।

राजनाथ का उद्धव पर हमला, कहा-

उन्होंने सत्ता के लिए ताक पर रखे सिद्धांत

पुणे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पुणे में उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं बालासाहेब ठाकरे का भी बहुत सम्मान करता हूं। मगर उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। इसका मुझे दुख है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी वही होता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को गले लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई है। जो भी कांग्रेस से जुड़ा है वह डूब जाएगा। महाराष्ट्र में यही हाल होने वाला है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति डूब जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना (उद्धव) और एनसीपी (शरद) का सहारा लिया है और उनका डूबना तय है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा और कुछ तीन से पांच राज्यों में लोकसभा चुनाव परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे।

फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा, डिजिटल मीडिया को जवाबदेह बनाना होगा: वैष्णव

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पारंपरिक मीडिया आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहा है, क्योंकि न्यूज पारंपरिक माध्यमों से डिजिटल माध्यमों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस समस्या का उचित समाधान किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए संबोधन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया के योगदान और आपातकाल के 'काले दिनों' के दौरान लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया के योगदान को स्वीकार किया। मीडिया के सामने चार प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करते हुए वैष्णव ने कहा, हालांकि पत्रकारों की एक टीम बनाने, उन्हें प्रशिक्षित करने, समाचार की सत्यता की जांच करने के लिए संपादकीय प्रक्रिया व तरीके अपनाने और सामग्री की जिम्मेदारी लेने के पीछे जो निवेश होता है, वह समय और धन दोनों के लिहाज से बहुत बड़ा है। लेकिन वे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक मीडिया के मुकाबले सौदेबाजी की शक्ति के मामले में इन प्लेटफार्मों की बढ़त बहुत असमान है। वैष्णव ने फेक न्यूज व गलत सूचना को वर्तमान में मीडिया और समाज की चार चुनौतियों के पहला स्थान दिया।

प्रमुख समाचार

राहुल के बैग की जांच, चुनाव आयोग के अधिकारियों की कार्रवाई

अमरावती। चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में कार्रवाई की जा रही है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बैग के साथ-साथ हेलीकॉप्टकर की भी जांच की जा रही है। इस कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना यूबीटी, भाजपा नेताओं के भी बैग की जांच की है। लेकिन इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भाजपा पर निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अमरावती में रैली करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर धामनगांव रेलवे के हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। इसे लेकर राज्य की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की टेओसा विधायक यशोमति ठाकुर ने चुनाव अधिकारियों से पूछा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दिन पहले झारखंड के दौरे पर रहे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति न मिलने पर खूब बवाल मचा था।

झांसी अग्निकांडः 10 नवजात जिंदा जले, चार सदस्यीय कमेटी गठित

लखनऊ। यूपी के झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात जिंदा जल गए। जबकि 16 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना को लेकर सरकार सख्त है। मामले में की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। टीम का नेतृत्व डीजीएमई करेंगे। बताते चलें कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। इस अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में शुक्रवार रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग में जलकर 10 बच्चों की मौत हो गई। घटना में अन्य 16 बच्चे घायल होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगी, उसमें कुल 55 बच्चे थे। घटना के बाद के बाद बात अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल में रखे आग बुझाने वाले उपकरण पर पहुंच गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अस्पताल में आग बुझाने के उपकरण एक्सपायर हो गए थे और अलार्म खराब थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार बच्चों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है।

आज बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

उत्तराखंड। उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर, रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले 16 नवंबर को वैदिक परंपराओं के अनुसार पंज पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी की पूजा होगी, और उन्हें कढ़ाई के प्रसाद का भोग अर्पित किया जाएगा। फिर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की जाएगी कि वे बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रहें। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि 17 नवंबर को शाम को कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बदरीनाथ के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी महिला वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी को श्री बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करेंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया 17 नवंबर को रात सवा 8 बजे से शुरू होगी। रात 9 बजकर 07 मिनट पर घृत कंबल ओढ़ाने के बाद, भगवान बदरीविशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को सुबह योग बदरी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। 17 नवंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलेगा। दिन भर मंदिर में पूजा होती रहेगी और दर्शन होते रहेंगे। शाम को कपाट बंद करने की पूजा 6:45 बजे शुरू होगी

अनुच्छेद 370 पर अपना स्टैंड किल्यर करे एनसी और कांग्रेस

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि उनकी पार्टी ने कभी भी अनुच्छेद 370 की बहाली के बारे में बात नहीं की। महबूबा गुरुवार को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुच्छेद 370 की वापसी पर खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। मुफ्ती ने कहा कि इस सरकार को जनता ने भारी जनादेश दिया है। उन्होंने इस पर गहरी आस्था जताई है। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा पारित प्रस्ताव में केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य की विशेष स्थिति को बहाल करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के लिए कहा गया था, जो अनुच्छेद 370 की बहाली पर अस्पष्ट और स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि नेकां और कांग्रेस सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पीडीपी ने यह भी कहा था कि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं था (अनुच्छेद 370 पर) और इसका अस्पष्ट उल्लेख किया गया था।

जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसा सपा का व्यवहारः योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अलीगढ़ में एक सार्वजनिक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला किया, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच एक समानता बताई गई। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम लीग के समान विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखी थी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना भी अलीगढ़ में ही हुई थी। अलीगढ़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके इरादे कामयाब हो गए। वही काम जो काम उस समय मुस्लिम लीग कर रही थी वही काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है। उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि याद रखें कि मुस्लिम लीग की नींव इस्लामाबाद या कराची या ढाका में नहीं थी। यहीं अलीगढ में था। खतरनाक इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। जो

धीमी न्यायिक प्रक्रिया के विकल्प पर सोचना होगा

उमेश चतुर्वेदी

उलेमा बनाम उत्तरी दिल्ली मामले पर सुनवाई के दौरान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थीं, इस मामले पर आए फैसले का अंदेशा उनसे हो गया था। सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसके लिए मानक प्रक्रिया बनाकर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के हाथ जरूर बांध दिए हैं। जैसा कि हर फैसले के साथ होता है, हर पक्ष अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोधी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं इसके समर्थक इस फैसले में भी कार्रवाई के लिए राह खोज रहे हैं। इससे साफ है कि बुलडोजर न्याय सिर्फ स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, ब्रेक नहीं बन पाएगा। स्पीड ब्रेकर तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार को धीमी करता है, जबकि ब्रेक गाड़ी को रोक देता है। यह फैसला भी कुछ इसी तरह का साबित होने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को नियंत्रित करते वक्त एक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहां आपराधिक मामलों की सुनवाई की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस तरह की देर लगती है, उसे अपराध करने वालों ने अपने लिए आड़ बना रखा है। बरसों तक धीमी गति से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का एक संदेश यह है कि ताकतवर चाहे तो अपराध करने के बावजूद प्रक्रिया की घुमावदार गलियों में न्यायिक फैसले को टाल सकता है। यह टालना इतना लंबा हो जाता है कि एक तरह से वह न्याय से इनकार हो जाता है। देर है पर अंधेर नहीं की सोच भी उबाऊ और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के सामने धुंधली होते-होते समाप्त हो जाती है। इसी घुमावदार और लंबी-धीमी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प बनकर बुलडोजर न्याय उभरा था। राज्य सरकारों ने इसे त्वरित न्याय के साधन के तौर पर अपनाया और देखत ही देखते अपराधमुक्त समाज की चाहत रखने वालों की चहेती बन बैठीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई की मानक प्रक्रिया बनाते हुए त्वरित न्याय के विकल्प या न्यायिक प्रक्रिया की घुमावदार गलियों को पूरी तरह नजरंदाज किया है। यही वजह है कि इस फैसले के बाद अपराधियों, गैंगस्टरों, असामाजिक तत्वों के उभार को लेकर समाज का एक बड़ा वर्ग सशंकित हो उठा है। देश की सबसे बड़ी अदालत होने के चलते सुप्रीम कोर्ट को इस सामाजिक सोच का भी संज्ञान लेना चाहिए और उसे भी आश्वस्त करना चाहिए कि उसके फैसले के बावजूद किसी गैंगस्टर, कोई अपराधी या समाज विरोधी तत्व को कमजोर तबके की जमीनों या सार्वजनिक संपत्तियों के अतिक्रमण का हक नहीं मिल जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तरी दिल्ली के एक मामले में दिया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीर पुरी में रामनवमी के दिन निकले जुलूस पर एक मस्जिद और उस इलाके से जुलूस पर हुए पथराव और उससे उपजी हिंसा के जवाब में दिल्ली नगर निगम ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई को सांप्रदायिक कार्रवाई का रंग देते हुए सेकुलर धारा के दिग्गज वकीलों मसलन कपिल सिब्बल आदि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भले ही सुनवाई इसी मामले की होती रही, लेकिन संदेश ऐसा गया मानो उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई हो रही है। इसकी वजह यह रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित न्याय के विकल्प के रूप में इसे अपनाया। तब उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर यह छवि बनाई गई कि वह सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम तबकों के खिलाफ ही बुलडोजर कार्रवाई करती है। जबकि योगी सरकार ने बिरादरी से ब्राह्मण लेकिन कर्म से माफिया और गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ भी इस कार्रवाई को किया। भदोही के बिरादरी से पंडित गैंगस्टर और राजनेता विजय मिश्रा की अतिक्रमित संपत्तियां भी उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर रहीं। लेकिन प्रचारित सिर्फ अतीक, मुख्तार जैसे मुस्लिम दबंगों और माफियाओं की संपत्तियों के खिलाफ हुई कार्रवाई ही की जाती रहीं। इस बहाने त्वरित न्याय के इस सरकारी विकल्प को हिंदुत्ववादी राजनीतिक दर्शन का ना सिर्फ नतीजा बताया गया, बल्कि यह नैरेटिव स्थापित कर दिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आम लोगों के बीच संदेश यही गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आया फैसला है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रचारित सिर्फ योगी सरकार रही, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि सरकारों ने भी की है। एक आंकड़े के मुताबिक, पिछले सात सालों में करीब 2000 अवैध अतिक्रमण बुलडोजर कार्रवाई में ढहाए गए। जिनमें सबसे ज्यादा करीब डेढ़ हजार मामले उत्तर प्रदेश के ही रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई से खाली कराई गई जमीनों को कमजोर तबकों में बांटा भी गया है। करीब सात सौ ऐसे प्लॉट बांटे जा चुके हैं। इसकी चर्चा कम हो रही है।

निश्चित तौर पर इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि किसी अपराधी के अपराध की कीमत उसका पूरा परिवार अपना घर गवांकर क्यों चुकाए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी का घर भी अगर सरकारी तंत्र के निशाने पर बना तो उसकी वजह उसका नियमित निर्माण नहीं, बल्कि अवैध कब्जा और अतिक्रमण रहा।

अब तक बुलडोजर कार्रवाई नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे में स्थानीय जिला अधिकारी और उप जिलाधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जिला अधिकारी की निगरानी में होगी और इसके लिए मान्य प्रक्रिया और नोटिस आदि देने की अवधि का पूरी तरह निर्वहण किया जाएगा। इस प्रक्रिया की राह में एक बाधा नजर आ रही है। जिला प्रशासन समय और काम के बोझ का बहाना बनाकर ऐसी कार्रवाइयों को टाल सकता है।

उत्तरी अबूझमाड़ में हुए मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर

■ मारे गये नक्सलियों के शव व हथियार बरामद

कांकेर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी अबूझमाड़ में कांकेर और नारायणपुर की सरहद से लगे महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षाबलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षाबलों के जवान सभी मारे गये नक्सलियों के शव एवं बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ में शामिल जवानों का दावा है कि इसके अलावा कई नक्सली घायल हुए हैं,। वहीं इस मुठभेड़ में दो जवानों को भी गोली लगी है, फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि नारायणपुर और कांकेर से लगे उत्तरी अबूझमाड़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद से लगे महाराष्ट्र सीमा पर नक्सली लीडर अभय समेत बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था, शनिवार सुबह अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस फोर्स नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंची तो नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं नक्सली

इस इलाके से महाराष्ट्र की ओर भाग न जाए इसके लिए कांकेर जिले से लगे गढ़चिरौली इलाके में सी-60 कमांडो को तैनात किया गया है।

बस्तर आईजी सुददराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि उत्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियो की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी सर्चिंग अभियान पर रवाना की गई थी। सर्चिंग के दौरान आज सुबह 8 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई, 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में अब तक 5 नक्सलियों के शव एवं बड़ी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी बरामद हुए हैं। उन्होने बताया कि मुठभेड़ में शामिल 2 जवान घायल हुए है, जिनकी स्थिति सामान्य व खतरे से बाहर है। दोनों घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जावेगी।

विस्फोटक के साथ 1 नक्सली भण्डरपदर आरपीसी अध्यक्ष गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना गादीरास से जिला बल की पार्टी ग्राम जीरमपाल व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान ग्राम जीरमपाल, चिंनापारा के जंगल से 1 संदिग्ध को सुरक्षा बलों के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पकड़े गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछ-ताछ करने पर अपना नाम कवासी जोगा पिता कवासी देवा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम भण्डारपदर थाना भेज्जी जिला सुकमा का होना तथा नक्सल संगठन में कोंटा एरिया कमेटी में भण्डरपदर आरपीसी अध्यक्ष के पद पर कार्य करना बताये। गहन पूछताछ करने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुचाने की नीयत से 1 थैले में विस्फोटक सामग्री को छूपाकर रखना बताया। जिसके निशानदेही पर 5 नग जिलेटिन रॉड, 4 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर लगभग 2.5 मीटर लगभग, 1 नग टिफिन, 1 नग इंजेक्शन सिरिंज, 14 नक्सल पर्चा को बरामद किया गया। उक्त कृत्य विधि विरूद्ध पाये जाने से आरोपी कवासी जोगा पिता देवा के विरूद्ध थाना गादीरास में अपराध क्रमांक 32/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल दाखिल किया गया।

धान खरीदी शुरू होते ही होने लगा अवैध धान परिवहन

महासमुंद प्रशासन का तगड़ा एक्शन

महासमुंद। धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान परिवहन और अवैध रखे हुए धान पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ जारी हो गयी है। पिथौरा के ग्राम मोहन्दा में दुकान और घर में धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए लगभग 1000 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करावाई किया गया।

अधिकारियों को सूचना मिली कि टिकेश्वर के दुकान और घर में बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। जिसके बाद राजस्व की टीम ने छापामार कारवाई की। टिकेश्वर से धान रखने के संबंध में दस्तावेज मांगे लेकिन पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में टिकेश्वर असमर्थ रहे। जिसके बाद प्रशासन ने धान को जब्त किया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

इसी तरह बसना के ग्राम अंकोरी में भी अवैध धान मिलने के मामले में कार्रवाई की गई। अंकोरी में विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। राजस्व की टीम ने छापामार कारवाई करते हुए दस्तावेज मांगे। जिस पर दोनों ग्रामीण अधिकारियों से बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने लगे। जिसके बाद अधिकारियों ने 879 कट्टा धान जब्त किया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। अधिकारियों से बदसलूकी करने वाले विशाल गजेंद्र को पुलिस के हवाले किया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा है कि धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर लगातार सख्ती से कारवाई की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। अवैध धान परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, मंडी उपनिरीक्षक और पटवारियों को निर्देश दिया गया है।

सक्ती नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद लापता

वार्डवासियों ने लगाए पोस्टर, कहा खोजकर लाईए

सक्ती। सक्ती नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्डवासियों ने मोर्चा खोला है. सक्ती नगरपालिका के ठाकुर मोहल्ला में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से एक सड़क की मांग कर रहे हैं।सड़क नहीं होने पर वार्डवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्डवासियों का कहना है कि जब भी चुनाव का सीजन आता है तो उनके पास हर नेता हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हमसे हर जरूरतों को पूरा करने का वादा किया जाता है।लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनप्रतिनिधि वार्ड में झांकने तक नहीं आते।

वार्डवासियों का कहना है कि 80 साल से भी अधिक समय हो गया। लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने हर बार जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटे और उनसे सड़क बनाने की मांग की लेकिन किसी ने भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।इसलिए वार्डवासियों ने एकजुट होकर पूरे वार्ड में अध्यक्ष और पार्षद के लापता होने के पोस्टर लगाएं

हैं।लेकिन चुनाव जाने के बाद कोई भी नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने पोस्टर हैं।ताकि उनको तलाशकर फिर से सड़क बनाने की मांग दोहराई जा सके।

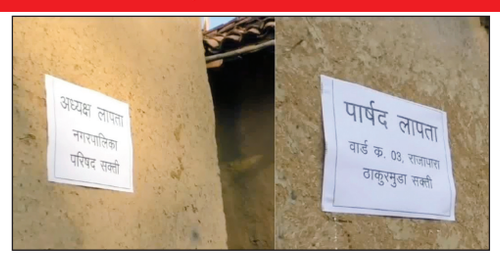

वार्डवासी पपीता बाई उरांव ने बताया हम लोग कई साल से अध्यक्ष और पार्षद से गुहार लगा रहे हैं।लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं मान रहा है।सड़क की जरुरत हैं,जब भी हम उनके पास जाते हैं,तो हां आएंगे कहकर टाल देते हैं।लेकिन साल दर साल गुजरते जा रहे हैं।लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में अब हम लोगों ने पोस्टर लगाया है।आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर विरोध करेंगे।

वार्डवासी सुमित उरांव ने बताया अध्यक्ष और पार्षद लापता हो गए हैं। हमारी रोड की समस्या सालों पुरानी है।हर बार वार्ड में आकर जनप्रतिनिधि बातें करते लगाकर विरोध किया है।यदि अब भी हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे।

आपको बता दें कि ठाकुर मोहल्ला में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। वार्ड के लोग खेत ओर पगडंडी से होकर नगर की ओर जाते हैं। वार्डवासियों का कहना है कि शासन प्रशासन से सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बिना सड़क के नरक की जिंदगी जी रहे हैं। बरसात होते ही खेत कीचड़ में बदल जाता है। कीचड़ को पार करके लोग शहर जाते हैं।अस्पताल में जाने पर कई बार मरीज देरी हो जाने के कारण नहीं बच पाता।इसलिए अब वार्डवासियों ने अब सड़क निर्माण को लेकर पहले पोस्टर और फिर आंदोलन करने का ऐलान किया है।

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम विवादों में घिरा

बालोद। जिले के आदिवासी ब्लॉक डौंडी के पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर विवाद पैदा हो गया है। सर्व आदिवासी समाज बालोद जिलाध्यक्ष तुकाराम कोर्राम ने कार्यक्रम की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन जनजातीय समाज को लेकर गंभीर नहीं है।

सर्व आदिवासी समाज बालोद के जिलाध्यक्ष तुकाराम कोर्राम ने आयोजन को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिरसा मुंडा को याद कर आदिवासी इस दिन मूलनिवासी आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन प्रशासन इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय समाज को डायवर्ड करने की साजिश रच रहा है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को आयोजन करने से पहले सर्व आदिवासी समाज का बैठक करना था।

वहीं गुरुनानक जयंती पर स्कूली अवकाश होने के बावजूद स्कूली बच्चों को स्कूली वेशभूषा पहनाकर आयोजन में भीड़ बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से आयोजन स्थल पर एकत्रित किया। आदिवासियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के एक भी पदाधिकारी नजर नहीं आए। आयोजन में कांकेर लोकसभा सांसद, विधायक, जिला व जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन भीड़ जुटाने में नाकाम रही।

आरपीएफ ने दो फर्जी टिकट चेकर को गिरफ्तार

■ कुमारघाट-अगरतला रेलखंड पर फर्जी तरीके से कर रहे थे टिकट की जांच

■ फर्जी टिकट चेकर हुसैन अली और कौशिक सरकार त्रिपुरा में पकड़े गए पुलिस ने भेजा जेल

रायपुर/बिलासपुर। रेलवे टिकट चेकर की वर्दी पहनकर पैसेंजर गाड़ी में यात्रियों के टिकट की जांच कर रहे दो फर्जी टिकट चेकरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों को धर्मानगर अगरतला रेल खंड में चलने वाली पैसेंजर गाडियों में संध्या के समय बिना प्राधिकार पत्र के गलत तरीके से टिकट चेकिंग करते हुए पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्जी टिकट चेकर हुसैन अली द्वारा 05676 धर्मानगर अगरतला पैसेंजर गाड़ी में टिकट चेकिंग की जा रही थी। इस ट्रेन में एस्कॉर्ट की ड्यूटी कर रहे रेल सुरक्षा बल के अजीत कुमार सरकार और अंजन पॉल को हुसैन अली की कार्य प्रणाली और गतिविधियों को देखकर संदेह हुआ। आरपीएफ जवानों ने फर्जी टीटीई हुसैन अली से पहचान पत्र और प्राधिकार पत्र दिखाने के लिए कहा। हुसैन अली ने पहले तो कहा कि वह एक नवनियुक्त टिकट चेकिंग कर्मचारी है और इसलिए टिकट की जांच कर रहा है, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दीमापुर के टिकट चेकिंग मस्टर रोल से भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया जिसमें हुसैन अली के फर्जी होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद हुसैन अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

इसी रेलखंड में चलने वाली पैसेंजर गाड़ी 05675 डाउन में काम कर रहे सीनियर टिकट चेकिंग कर्मचारी सुबर्जित पॉल ने कौशिक सरकार नामक एक फर्जी टिकट चेकर को संदेह के आधार पर धड़ दबोचा। कौशिक सरकार ने पहले बयान दिया कि उसको टिकट चेकर के रूप में रेलवे में नौकरी मिली है। लेकिन किसी प्रकार का अथॉरिटी लेटर या पहचान पत्र दिखाने में वह असफल रहा जिसके बाद सुब्रजीत पॉल ने फर्जी टिकट चेकर कौशिक सरकार को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

साक्षात्कार 18 की जगह अब अब 27 नवंबर को

बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला/जनपद स्तर के विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु तकनीकी सहायक प्रोग्रामर का 18, नवम्बर 2024 को आयोजित साक्षात्कार अपरिहार्य कारण से स्थगित हो गया है। यह साक्षात्कार 27 नवंबर 2024 को कलेक्ट्रेट जिला बेमेतरा कक्ष कमांक 01 में ही होगा। विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक पद के चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाना था। अब यह साक्षात्कार लिए जाने वाले पदों हेतु तिथि, समय एवं स्थान क्लेक्ट्रेट जिला बेमेतरा के कक्ष क्रमांक 1 (कलेक्ट्रेट चेम्बर) में होगा। तकनीकी सहायक (कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची के 1 से 30 तक के अभ्यर्थी) दिनांक 22.11.2024 सुबह 11 बजे से होगा। तकनीकी सहायक (कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची स.क्र. 01 से 60 तक के अभ्यर्थी) 25 नवंबर सुबह 11 बजे से, तकनीकी सहायक प्रोग्रामर (कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची के स.क्र. 1 से 15 तक के अभ्यर्थी का 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से होगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

गौतम सोना ने पुलिसकर्मियों पर जमाई धौंस, निकाली हेकड़ी

दुर्ग। दुर्ग में पुलिस ने गृह मंत्री का करीबी बताकर पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था पुलिस उसे रोककर पुछताछ कर रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता गौतम सोना पुलिस के साथ बहस करने लगा। पुलिस ने बीजेपी नेता को थाने ले जाकर उसकी लग्जरी कार को जब्त कर लिया है। दरअसल देर रात शराब के नशे में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का रहने वाला गौतम सोना कार में घूम रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोककर पूछताछ की तो खुद को डिप्टी सीएम विजय शर्मा का करीबी बताकर पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाने लगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी गौतम सोना के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रववाई की जा रही है।

अधिकारियो से बदसलुकी और दुर्व्यवहार करने पर जेल भेजा

महासमुंद। बसना अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे के निर्देशन में बीते कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी मे विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में क्रमशः 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल 879 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करावाई किया गया। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी के विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर मे बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। तत्पश्चात राजस्व की टीम ने छापामार कार्रवाई की और दस्तावेज मांगे, परंतु पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत करवाई कर जब्त किया गया था। कारवाई के पश्चात जाँच मे गए अधिकारियो के साथ विशाल गजेंद्र द्वारा बदसलुकी और दुर्व्यवहार किया गया साथ ही देख लेने की धमकी भी दी गई। उक्त कृत्य के चलते अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज खांडे द्वारा कार्रवाई करते हुए विशाल गजेंद्र को जेल भेजा गया।

लाहिड़ी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल मेले का आयोजन

चिरमिरी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आजादी की लड़ाई के क्रांतिवीर पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर लाहिड़ी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जीएम कॉम्प्लेक्स में आयोजित बाल मेला कार्यक्रम ,नगर पालिक निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर के.डोंमरू रेड्डी, एसईसीएल महिला संपदा समिति की अध्यक्ष श्रीमती संगीता श्रीवास्तव और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रो.भागवत प्रसाद दुबे के आतिथ्य में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। बाल मेला में बच्चों एवं अभिवावकों के साथ साथ आए हुए अतिथियों का उत्साह देखते बन रहा था। आगंतुकों द्वारा स्कूल के चारों हाउसों यथाऱ्दादू लाहिड़ी, आर के मालवीय,राम कुमार दुबे,नरसी भाई पटेल हाउसों के छात्रों द्वारा तैयार किये विभिन्न स्टालों में जाकर बच्चों द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आनंद लेकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के प्रबंधक राणा दास, सचिव वाचस्पति दुबे, प्राचार्या श्रीमती अमृता ब्रह्मचारी एवं सुनील कुमार सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे।

लायंस क्लब चिरमिरी वरदान द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा

चिरमिरी। लायंस क्लब चिरमिरी वरदान द्वारा बड़ा बाजार शिशु मंदिर विद्यालय के भवन में सिग्नेचर प्रोजेक्ट क्षितिज के पार होनहार के तहत अपनी पाठशाला वरदान संस्कार केन्द्र संचालित कर रहा है जिसमें कक्षा पहली से आठवीं तक के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लगभग 50 बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का कार्य मुनमुन जैन के साथ प्रिया केसरवानी, सुमन अग्रवाल, प्रीति अग्रहरी, सुनीता सोनी, अरुंधती तिवारी द्वारा किया जाता है व समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है इसी क्रम में बाल दिवस व गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं गई। कार्यक्रम का संचालन शुभ्रा जैन द्वारा किया गया जिसमें नृत्य, भजन, कविताएं आदि प्रस्तुतियों देकर बच्चों में आत्मविश्वास और हुनर को पहचानने की क्षमताएं विकसित होती हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रणव चक्रवर्ती, विशिष्ट अतिथि अल्पना जैन, क्लब अध्यक्ष मुनमुन जैन, सुमन अग्रवाल आदि की उपस्थिति रही।

भिलाई में युवक को चाकू से गोदा, चाय पीने निकले थे तीनों

दुर्ग। भिलाई में फिर एक बार फिर युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या का दी गई। रामनगर तालाब के पास अलसुबह एक युवक और नाबालिग ने मिलकर अपने ही दोस्त की चाकू से वार कर हत्या कर दी। तीनों दोस्त रामनगर मुक्तिधाम तालाब के पास चाय पीने के दौरान किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छावनी थाना और वैशाली नगर पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जहां पर तीनों दोस्तों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दो दोस्तों ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। आस पास के लोगों ने घायल को अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से फरार आरोपियों की पतासाजी करने पर आरोपी भागने की फिराक में पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

रेल्वे पुलिस ने यू-ट्यूबर दोस्त से मिलने घर से निकले नाबालिग को जेवर-नगदी समेत परिजनों को सौंपा

राजनांदगांव। अपने यू-ट्यूबर दोस्त से मिलने 5 लाख से ज्यादा के सोने-चांदी के जेवर व नगद राशि लेकर घर से गुस्से में बिना बताए निकले एक नाबालिग को रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स राजनांदगांव की मदद से सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को ड्यूटी के दौरान राजनांदगांव स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर रेल सुरक्षा बल राजनांदगांव की प्रभारी निरीक्षक तरूणा साहू, उनि पीएल जुमड़े, प्र.आ. एनके साहू व आरक्षक मनीष पटेल गाड़ी सं. 18029 शालिमार एक्सप्रेस स्टेशन के चेकिंग के दौरान एसी कोच के पास एक लडका डरा-सहमा दिखने पर उससे पूछताछ की गई।

नाबालिग महाराष्ट्र का रहने वाला बताया और वह तिरोड़ा स्टेशन से इफ्टी नं. बी-0914631 टिकट गोंदिया से शालिमार बनवाया था तथा अपने यू-ट्यूबर दोस्त से मिलने के लिए घर से बिना बताए सोने-चांदी के गहने और नगदी लेकर कोलकाता जा रहा था। संदेह के आधार पर पूछताछ करने पर बताया कि वह अपने मां-बाप से नाराज होकर गुस्से में घर से निकल गया है। उक्त नाबालिग को रेसुब पोस्ट राजनांदगांव में लाया गया। उसके पास एक काले रंग का पिबैग था। बैग को खोलकर दिखाने पर उसमें पहनने के कपड़े और घर में किसी सदस्य को बिना बताए 54 हजार 500 रुपए नगद व सोना गहना कुल अनुमानित 4 लाख 33 हजार रुपए, एक मोबाइल कीमती 13 हजार रुपए कुल कीमती 5 लाख 500 रुपए बैग में पाया गया।

नाबालिग के पास बंद हालत में मिले मोबाइल को चालू कराकर लड़के के परिजनों से संपर्क कर परिजनों द्वारा बताया गया कि उक्त नाबालिग गुस्से में घर से सोना-चांदी का जेवर एवं नगदी रुपए लेकर चला गया है। जिसके बारे में पतासाजी कर रहे थे। लडके को रोककर रखे रहने की बात कही। तत्पश्चात रात करीब 10 बजे उसके परिजन पोस्ट में आए, पूछने पर अपनी पूरी जानकारी दी। वेरीफाई करने के उपरांत उक्त नाबालिग के पास रखे नगदी रकम व गहने को पोस्ट में उपस्थित गवाहों के समक्ष परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजन अपने नाबालिग बेटे के साथ नगदी व गहने तथा मोबाइल समेत बैग को सही सलामत पाकर रेसुब राजनांदगांव का आभार व्यक्त किया।

विधायक प्रणव की उपस्थिति में गौरेला में हिंदू सम्मेलन का आयोजन

पेंड्रा। परम शांति धाम गौरेला में युवा शक्ति के राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण के उद्देश्य से विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संतों व हिंदू बंधुओं व भगनीयों की उपस्थिति सराहनीय रही। आश्रम के प्रमुख स्वामी परमात्मानंद ने कार्यक्रम को संबोधित किया और हिंदुओं को जागृत करने के लिए व्याख्यान दिया। स्वामी ने कहा कि यह समय हिंदुओं को एकजुट रहने का है। स्वामी परमात्मानंद जी के संबोधन के पश्चात कथा गीता वचन एवं भजन प्रतियोगिता में भाग लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए । कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुद्धिस्ट कुंगफू फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के प्रेसिडेंट भरत विश्नोई उपस्थित थे।

विश्नोई ने युवा शक्ति को स्वस्थ रहने और देश के लिए कार्य करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने उपस्थित युवा शक्ति को आत्मरक्षा के गुर भी बताएं । कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से पधारे स्वामी देवेश्वरानंद एवं स्वामी शुद्धात्मानंद ने भी उपस्थित बंधुओं और भगनीयों को संबोधित किया और उन्हें जागृत रहने के लिए कहा।

मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची का संस्था के सदस्यों ने सम्मान किया। विधायक श्री मरपच्ची ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए संस्था को भवन निर्माण के लिए 10 लाख

रुपए देने की घोषणा की। संस्था के अध्यक्ष डां. ललित मखीजा एवं सचिव पुरुषोत्तम नाथ पिपरहा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित विशाल हिंदू समूह को धन्यवाद अर्पित किया। संबोधनों के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सभी सज्जनों और माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया ।

कार्यक्रम में आश्रम के संस्कृत विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सभी का मन मोह लिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष हर्ष छाबरिया एवं उपाध्यक्ष संदीप सिंघई ने सभी नगर वासियों एवं ग्राम वासियों को इस सम्मेलन में सादर आमंत्रित किया एवं सभी प्रतियोगियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं प्रदान की है।

संक्षिप्त समाचार

जशपुर के मुंडारी नर्तक दल के कलाकारों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

रायपुर। राजधानी रायपुर में आयोजित दो

दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस में अपनी कला का प्रदर्शन करने आए जशपुर जिले के मुंडारी नृत्य दल के कलाकारों ने यहां मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि राजधानी के मुख्य समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन करके उनके दल के सदस्य काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से मिले अवसर के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने इन कलाकारों से इनके गांव का हालचाल भी पूछा, जिसके जवाब में दल के सदस्यों ने बताया कि वे लोग बादलखोल अभ्यारण्य के बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत बछरांव के निवासी हैं। यहां मुड़ा, नगेशिया, पहाड़ी कोरवा और उरांव जनजाति के परिवार निवासरत हैं। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित है। तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में इन लोगों ने सात स्ट्रीट लाइट की मांग मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आश्वस्त किया। लोक कलाकारों के इस दल में प्रतिभा मुंडा, मीना मुंडा, शांता, विष्णु बरला, रामदयाल, सुनीता, अनुराधा, अमिता बरला, विष्णु मांझी और विश्वनाथ प्रधान आदि शामिल थे।

राज्यपाल डेका ने हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों को सराहा

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने राजधानी

दिल्ली में गरीब महिलाओं एवं बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्था हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारिका स्थित संस्था का भ्रमण किया। उन्होंने संस्था के कार्यों की जानकारी ली। यह संस्था छोटे-मोटे रोजगार कर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं उनके व्यक्तित्व विकास, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। श्री डेका ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की साथ ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी स्वास्थ्य कैंप लगाने का अनुरोध किया। श्री डेका के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में उक्त संस्था द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आगामी माह में किया जाएगा। राज्यपाल ने उपस्थित बच्चों से बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खींचवाई।

प्रान्तीय अखण्ड ब्राह्मण समाज ने की महाआरती और दीपदान

रायपुर। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महादेव घाट में श्रीमती भारती किरण शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति एवं प्रदेश संयोजक पंडित मेघराज तिवारी के निर्देशन में दीप-दान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पं. मेघराज तिवारी, पंडित हेमलाल शर्मा के द्वारा विधि विधान द्वारा पूजन कर महाआरती की गई जिसमें ईश्वर प्रसाद शर्मा, प्रीति शुक्ला, पूर्णिमा तिवारी, सरिता तरुण शर्मा,नेहा शर्मा, शजिन्ता शुक्ला, किरण लता पाठक, पूर्णिमा दुबे, यश महराज व संगठन के समर्पित सदस्यों, पदाधिकारियों द्वारा 101 दीप जलाकर पूजा आरती कर नदी में दीप प्रज्जलन कर प्रवाहित किया गया व मंगलकामनाएं की गयी, साथ ही सर्व समाज के समृद्ध, दीर्घायु,व यशस्वी होने की की कामना की गयी।

जशपुर में प्राकृति आपदा में हुए राजेन्द्र के देहांत के उपरांत हुई घटना की जांच के लिए भाजपा ने गठित की चार सदस्यी समिति

रायपुर। जनपद पंचायत मनोरा ग्राम पंचायत हररी डेंगिनी (कोर्कोट) विधानसभा जशपुर जिला जशपुर में प्राकृति आपदा में श्री राजेन्द्र चोराट के देहांत के उपरांत हुई घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एक 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थान का दौरा कर इस विषय से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को 7 दिवस के अंदर सौंपेगी। समिति में श्री शिवरतन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा संयोजक, श्रीमती रेणुका सिंह, विधायक, भरतपुर-सोनहत, राधेश्याम राठिया, सांसद रायगढ़ तथा श्रीमती गोमती साय, विधायक पत्थलगांव सदस्य के रुप में शामिल है।

सतपाल फार्म हाउस में हुक्का पीते 7 गिरफ्तार

रायपुर। ग्राम पिरदा स्थित सतपाल फार्म हाउस में हुक्का पीते 7 आरोपियों को विधानसभा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने 8 हुक्का पॉट के साथ दस हजार रुपए कीमत का 200 ग्राम फ्लेवर भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों में शेख सागर पिता शेख नवाबुद्दीन, शोएब आलम पिता अली हैदर, मनु शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा, श्रेष्ठ शर्मा पिता स्व. अजय शर्मा, अनमोल जदवानी पिता स्व. दिलीप जदवानी, विनेश लालवानी पिता देवपाल लालवानी और संजय महानंद पिता अनुजा महानंद शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर उप मुख्यमंत्री साव ने बताया

सभी स्टैक होल्टर से की गई है चर्चा

रायपुर। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बहुत अच्छी नीति बनी है। सरकार में हमारे उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग नीति बनाई है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, और उद्योगपतियों से भी सलाह ली गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि एक लंबे के समय के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टैक होल्डर से चर्चा करने के साथ राज्य की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से विचार करके औद्योगिक नीति 2030 बनाई गई है। हमारी उद्योग नीति केवल कुछ एरिया तक सीमित

ना रहे, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर मिले। रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के रोजगार में योगदान दे।

वहीं शराब घोटाले पर कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने 5 साल के कार्यकाल को क्यों भूल गए हैं। सैकड़ों करोड रुपए का शराब घोटाला किया। शराब बंदी का वादा करके धोखा किया।

गली-गली में शराब कोचियों के माध्यम से शराब भेजा। शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ में राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह की आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट में शराब प्रेमियों के लिए एप लांच किए जाने पर कसे गए तंज पर उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि शराब की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है।

ट्रेनों के रद्द होने पर कही यह बात

वहीं त्योहारों के बाद 24 ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा सभी ने देखी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधा में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल का काम दोहरी तरीके से हो रहा है, तो थोड़े अवरोध करनी पड़ते हैं, आगे सब ठीक होगा।

चित्रकोट में होगी बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक

सीएम साय समेत कई नेता होंगे शामिल

जगलदपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार बस्तर में विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे।

बैठक में प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में बस्तर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बैठक के मद्देनजर चित्रकोट जलप्रपात को 2 दिनों 17 व 18 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है।

बस्तर कलेक्टर, एसपी और बस्तर आईजी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर एसपी शलभ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के मूवमेंट वाले इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। जगह-जगह चेक पोस्ट लगाकर सुरक्षा जांच की जा रही है। होटल व लॉज की भी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश के 14 स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत अक्टूबर व नवंबर माह में अस्पताल का किया था मूल्यांकन

- स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई, कहा मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार हो रही बेहतर

रायपुर। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अक्टूबर व नवंबर माह में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुणवत्ता आश्वासन के मानकों पर खरा उतरने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही हैं और 14 शासकीय अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिलना इसी का नतीजा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महासमुंद ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र भदरसी को 91.29 प्रतिशत, बड़े टेमरी को 90.27 प्रतिशत, झलप को 91.93 प्रतिशत व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा को 88.89 प्रतिशत के साथ सूरजपुर ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र नवापाराकला को 76.09 प्रतिशत, धरमपुर को 87.75 प्रतिशत व कांकेर जिले आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र मुसरपट्टा को 94.2 प्रतिशत, पीवी89 को 85.58 प्रतिशत, कोदागांव को 93.36 प्रतिशत, माकरीखुना को 81.54 व बलौदाबाजार ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद् ठेलकी को 86.83 प्रतिशत, रायगढ़ जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र छर्राटानगर को 82.39 प्रतिशत, बस्तर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जमावड़ा को 88.99 प्रतिशत व रायपुर ज़िले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सिलयारी को 88.15 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व विगत माह भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया गया। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

कैडेवरिक शपथ देहदान दाता के प्रति आभारयुक्त समर्पण: डॉ. नेरल

रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के एनाटॉमी विभाग में प्रथम वर्ष के एम.बी.बी.एस छात्रों को कैडेवरिक ओथ (मृत देह शपथ) दिलाई गयी। इस अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. जागृति अग्रवाल ने इस उपलक्ष्य पर समस्त छात्रों को कैडेवरिक शपथ की महत्ता से अवगत कराया। इस परिपेक्ष्य में उन्होंने कहा कि कैडेवर को चिकित्सा छात्र का प्रथम शिक्षक माना जाता है क्योंकि चिकित्सा पाठ्यक्रम की आधारशिला मानव शरीर रचना पर आधारित है। उन्होंने इस अवसर पर देहदान करने वाले व्यक्तियों को यह कहते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया कि इनका त्याग न केवल चिकित्सा छात्रों को बेहतर डॉक्टर बनाने में मददगार होगा, अपितु इस त्याग से पूरे समाज का कल्याण होगा क्योंकि यही छात्र कालावधि में डॉक्टर बनकर समाज को अपनी सेवाएं देंगे।

तत्पश्चात मुख्य अतिथि डॉ. अरविंद नेरल के द्वारा एम.बी.बी.एस. सत्र 2024 के नव प्रवेशित 230 छात्रों को कैडेवरिक शपथ दिलाई गई। इस शपथ में छात्रों द्वारा देहदाता के त्याग

को धन्यवाद देते हुये उनकी देह के प्रति अभिवादन व्यक्त किया गया तथा उनकी निजता एवं गोपनीयता को सम्मान देने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर जनमानस में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। डॉ. नेरल ने अभिभाषण में अपने एम.बी.बी.एस. के दिनों को याद करते हुये कैडेवर की आवश्यकता तथा उसकी उपयोगिता बतायी। उन्होंने इस त्याग को सर्वोच्च त्याग के रूप में परिभाषित किया। अब तक कुल 124 बार रक्तदान कर चुके डॉ. नेरल ने एक बार फिर दूसरों के लिये उदाहरण प्रस्तुत करते हुये यह बताया कि उन्होंने स्वयं भी देहदान का प्रण लिया हुआ है तथा उनके 40 वर्षों के चिकित्सकीय जीवन में उनका यह प्रण उनके शैक्षणिक मातृ संस्था को समर्पित है। इस अवसर पर एनाटॉमी विभाग के सह-प्राध्यापक डॉ. प्रवीण कुर्रे, डॉ. दिवाकर धुरंधर, डॉ. प्रवीण बंजारे, डॉ. संगीता खरे, सहायक प्राध्यापक डॉ. दीप्ति चंद्राकर आदि उपस्थित थे।

पटवारियों ने अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप

17 को बनेगी आगे की रणनीति

रायपुर। संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे प्रदेश के पटवारियों पर आला अफसरों द्वारा अवकाश के दिन भी दबाव डालकर काम लेने से अब नाराजगी फूट रही है। पटवारियों ने डरा-धमकाकर काम लेने के खिलाफ अब मोर्चा खोलने का मन बना लिया है।

वहीं तीन माह पूर्व दिए गए आश्वासन को नजरअंदाज करने पर भी रणनीति तय होगी। राजधानी में 17 नवंबर को राजस्व पटवारी संघ जुटेगा। इस दौरान राज्य सरकार के कोरे आश्वासन और शीर्ष अधिकारियों की प्रताड़ना पर मंथन कर फैसले लिए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा मौखिक समझौते से पलटने के अलावा अफसरों की प्रताड़ना के खिलाफ राजस्व पटवारी संघ रणनीति तय करेगा।

संघ ने इस बात पर विरोध जताया कि संसाधानों के अभाव में भी आला अफसर

उनसे 6जी की स्पीड से दबावपूर्वक काम लेने धमकाने लगे हैं। अवकाश के दिनों में भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आधी रात को वॉट्सएप के जरिए मैसेज डालकर तत्काल जानकारी मांगने कहा जाता है। जमीनी समस्याओं को नजरअंदाज कर समूह के कार्यों को अकेले पटवारियों से करने दबाव बनाया जा रहा है। एक ही समय में कई कार्यों को तत्काल नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी देकर प्रताड़ित करने के खिलाफ भी मोर्चाबंदी होगी।

लोधेश्वरधाम में इस बार के दीपावली मिलन समारोह में समाज के चार विधायक होंगे शामिल

कवि लोधी विजय कुमार बघेले अपनी कविताओं से गुदगुदायेंगे

रायपुर। राजधानी रायपुर के लोधेश्वरधाम में इस बार का दीपावली मिलन समारोह कुछ खास रहने वाले हैं जब इसकी ख्याति व लोकप्रियता से प्रभावित होकर समाज के चार विधायक मंच पर मौजूद रहेंगे। 24 नवंबर को होने वाले इस भव्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। छत्तीसगढ़ से बाहर प्रांत से स्वजातीय बंधु जुटेंगे। कलियुग की मीराबाई लोधी शिवांगी दीदी की भक्ति गंगा बहेगी वहीं कवि लोधी विजय कुमार बघेले अपनी कविताओं से गुदगुदायेंगे।

लोधी क्षत्रिय समाज चंगोराभाठा इकाई के सचिव प्रहलाद दमाहे ने बताया कि साल दर साल आयोजन की भव्यता बढ़ते जा रही है। समाज के गौरव एटा(यूपी)के विधायक विपिन वर्मा (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त),बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे,लांजी के विधायक राजकुमार कुर्रहे व खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलाम्बर शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन वर्मा के नेतृत्व में लोधेश्वर धाम

(कुम्हारी टोल प्लाजा के पास) लोधेश्वर भगवान मंदिर का भूमिपूजन भी होगा।

लोधी क्षत्रिय समाज चंगोराभाठा रायपुर छत्तीसगढ के तत्वावधान में दीपावली मिलन समारोह, वार्षिक, परिचय सम्मेलन एवम स्मारिका विमोचन समारोह अलग अलग सत्र में आयोजित है। सभी कार्यक्रम लोधेशवरधाम मे रविवार 24 नवंबर को संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी-लोधा-लोध राष्ट्रीय महासभा के पदाधिकारीगण , सदस्यगण भी विशेष रूप से शामिल होगे। इस कार्यक्रम की जोर-शोर से तैयारी चल रही है। लोधी समाज की बेटी कलियुग की मीराबाई से विख्यात लोधी शिवांगी दीदी का आगमन छत्तीसगढ ही नही अपितु विदर्भ, बालाघाट, जबलपुर, मंडला गोदिया आदि क्षेत्रों मे से प्रथम बार लोधेशवरधाम में हो रहा है। जो अपनी ओजस्वी वाणी से भक्ति की गंगा बहायेंगी। वरिष्ठ कवि लोधी विजय कुमार बघेले, तुमसर महाराष्ट्र से अपने कविता के माध्यम से गुदगुदायेंगे।

पिछले 11 महीनों में पीएम आवास योजना के निर्माण में आई तेजी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए सर्वेक्षण शुरू, नए हितग्राहियों को भी अब मिलेंगे आवास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

मध्यम वर्ग को संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। उल्लखेनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 6 लाख रुपये है और उसका सौदा 10 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपये देना पड़ता था। इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइड लाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। 6 लाख रुपये की गाइड लाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 10 लाख में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 6 लाख के 4 प्रतिशत के हिसाब से 24 हजार रुपये देय होगा। इस तरह 16 हजार रुपये की बचत होगी। खास बात यह है कि इस संशोधन से मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

इतिहास की जमीन पर वर्तमान की लड़ाई

नितिन यादव

महाराष्ट्र का औरंगाबाद वह जिला है, जहां पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो देवगिरी का किला भी है। देवगिरी के किले को अपना केंद्र बनाने के लिए ही मुहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से यहां दौलताबाद लाने का फैसला किया था। तुगलक तो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन यह जिला आज पूरे मराठवाड़ा की राजनीति की राजधानी कहा जाता है। जिले का नाम तो छात्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है, पर विधानसभा क्षेत्रों के नामों में अभी औरंगाबाद नाम जुड़ा है। चुनावी राजनीति में भी इतिहास के किस्सों को वोट को साधने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। देखना है कि छत्रपति शिवाजी के बेटे के नाम पर रखे गए जिले और शहर का नाम, इसका इतिहास वर्तमान में रूझान किस ओर ले जाएगा। पिछले कुछ चुनावों से यह जिला शिवसेना का गढ़ रहा है। शिवसेना टूटी, तो कई विधायक एकनाथ शिंदे के पाले में आ गए। पूरे जिले में देखा जाए तो लड़ाई शिवसेना शिंदे बनाम शिवसेना यूबीटी के लिए बीच ही है। शहर की दो सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी एक सीट पर मजबूत दावेदारी कर रही है। जिले में कुल नौ सीटें-औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पश्चिम, गंगापुर, फुलंबरी, वैजापुर, कन्नड़, पैठन और सिलौड हैं। पिछले चुनाव में यहां से शिवसेना से जीते छह विधायकों में से पांच शिवसेना शिंदे गुट के साथ आ गए, तो कन्नड़ से विधायक उदय सिंह राजपूत उद्धव खेमे में ही रहे। अब शिंदे गुट का भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण कुछ भाजपाइयों ने भी पाला बदल लिया। औरंगाबाद पश्चिम, वैजापुर और सिल्लौड़ से भाजपा के कार्यकर्ता इस बार शिवसेना के उद्धव खेमे से ताल ठोक रहे हैं। जालना से भाजपा से सांसद रहे राव साहब दानवे की बेटी संजना जाधव कन्नड़ से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार हैं। उनका सामना उद्धव गुट के विधायक उदय सिंह राजपूत से तो है ही, अपने पति हर्षवर्धन जाधव से भी है, जो निर्दलीय मैदान में हैं। हर्षवर्धन दो बार विधायक रहे हैं। उनके माता और पिता दोनों विधायक रहे हैं। शिवसेना के दोनों गुट इस बात पर अड़े हैं कि जनता को कैसे बताया जाए कि किसने किसका साथ क्यों छोड़ा। शिंदे गुट के कार्यकर्ता सचिन का कहना है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करने वालों को अब जनता वोट नहीं देगी। वहीं, उद्धव ठाकरे समर्थक गणेश का मानना है कि सत्ता के लिए पार्टी को तोड़ने वालों से वोटर जवाब लेगा। पिछले चुनाव की तरह भाजपा फुलंबरी, औरंगाबाद पूर्व और गंगापुर से मैदान में है। पैठन, मध्य, पश्चिम, वैजापुर, कन्नड़, सिलौड से शिवसेना उद्धव गुट लड़ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर जिला यानी औरंगाबाद की चुनावी लड़ाई का सबसे पहला नारा इतिहास से ही जुड़ा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विशाल रैली को संबोधित करते हैं, तो वह भी छत्रपति शिवाजी राव और संभाजी राव के अभिवादन से शुरुआत करके महायुति गठबंधन की शिंदे सरकार को बधाई देते हैं। दरअसल, इस सरकार ने ही जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया। पीएम ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के लोग औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। जब उद्धव ठाकरे ने रैली की, तो उन्होंने कहा कि संभाजीनगर नाम रखने का प्रस्ताव उनकी सरकार में ही हो गया था। खास बात यह भी है कि शिवसेना के दोनों ही गुट बाला साहब ठाकरे की विरासत की बात कर रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि नाम बदलने का मुद्दा सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने ही उठाया था, जिसे एकनाथ शिंदे सरकार ने पूरा किया। पीएम मोदी भी अपने भाषण में बाला साहब ठाकरे के सपने की बात करते हैं। कहा जाता है कि एक दौर में यहां के मराठवाड़ सांस्कृतिक मंडल के मैदान में बाला साहब की रैली के बाद पूरा चुनावी माहौल बदल जाया करता था। अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे ने इसी मैदान से रैली की है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही मराठा आरक्षण पर सधी हुई राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार खेमा इस तरह का प्रचार कर रहा कि भाजपा इसके खिलाफ है। दरअसल, मराठा आरक्षण देने की शुरूआत देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। दस प्रतिशत इब्ल्यूएस कोटे में से आरक्षण दिया गया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार के समय कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद फिर से यह दिया गया। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल की अगुआई में मराठा को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का आंदोलन किया गया। युवाओं में जरांगे का भी असर है।

बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम रोक के श्वेत और स्याह पक्ष

कमलेश पांडे

राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने दो टूक कहा है कि जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह से अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिराती है कि वह आरोपी है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। क्योंकि एक घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। महिलाओं और बच्चों को बेघर होते देखना सुखद दृश्य नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घर/दुकान व अन्य निजी संपत्तियां ध्वस्त किए जाने से जुड़े नियम तय किए हैं।

सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। क्योंकि न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं। इसलिए कार्यपालिका अपने मूल कार्य को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक उपाय नहीं कर सकते। जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के कारण अभियुक्त/दोषी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह से अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। अगर केवल आरोप के आधार पर वह उसका घर गिरा देती है, तो यह कानून के शासन के मूल सिद्धांत पर आघात होगा। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को गिराने का फैसला नहीं कर सकती। कार्यपालिका के हाथों की ज्यादतियों से कानून के सख्त हाथ से निपटना होगा। हमारे संवैधानिक मूल्य सत्ता के ऐसे किसी भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। इसे न्यायालय द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में, कार्यपालिका कानून को अपने हाथ में लेने और कानून के शासन के सिद्धांतों को दरकिनार करने की दोषी होगी। अनुच्छेद 19 के अनुसार आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है।

इससे स्पष्ट है कि %बुलडोजर जस्टिस% पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सात बड़ी बातें कही है, जो निम्नलिखित हैं- पहला, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं बन सकती।

दूसरा, बिना उचित प्रक्रिया के आरोपी के घर को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। तीसरा, दोषी ठहराए जाने पर भी उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। चतुर्थ, मुकदमे से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता। पंचम, नगरपालिका कानूनों के लिए भी कानून का अनुपालन अनिवार्य है। छठा, लोगों को ध्वस्तीकरण नोटिस का जवाब देने और उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सातवां, अगर अधिकारी कुछ समय पहले उनकी मदद कर दें तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

यहां तक तो ठीक है, पर सीधा सवाल है कि जब किसी भी प्रकार के संगठित अपराध को रोकने के लिए सिविल प्रशासन के समक्ष त्वरित फैसले लेने व सख्त निर्णय करने की जरूरत होती है, तो इस प्रकार उसके हाथ बांधना क्या उचित है। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर न्याय तक की प्रशासनिक प्रक्रिया पर न्यायपालिका में जैसे-जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके मुताल्लिक जो-जो स्थगनादेश/न्यायदेश आ रहे हैं, क्या वह उचित है? जनता के व्यापक हित में है? शांति-व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम है! तो जवाब होगा- बिल्कुल नहीं।

भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लायी जाने वालीं लक्षित जनहित याचिकाओं पर एक के बाद एक आये स्थगनादेश/न्यायादेश समकालीन चिंता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का भी विषय बन चुके हैं। क्योंकि ऐसा करने वालों के विचार और लक्ष्य अलग अलग होते हैं, जिसकी बारीक मीडिया पड़ताल जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेहतर शासन व्यवस्था बदलते वक्त की अनिवार्य मांग है जिसे कायम रखने में मौजूदा कानून व्यवस्था विफल प्रतीत होती आई है। लिहाजा, बेहतर तो यही होगा कि हरेक समसामयिक मुद्दे पर जनमत सर्वेक्षण करवाकर लोगों की स्पष्ट राय भी जान ली जाए, क्योंकि हरेक अच्छे या बुरे फैसले से सबसे ज्यादा उनकी ही तकदीर और तदबीर प्रभावित होती है।

यह कौन नहीं जानता कि एक तरफ कुछ लोग और उनका समूह कतिपय कानून की आड़ लेकर, एनजीओ या जनहित याचिका का सहारा लेकर सिस्टम और उसकी लोकोपकारी व्यवस्था को तबाह किये हुए हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और होता है और साधन कुछ और। इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी आसानी से मिल जाती है और आंतरिक मदद लेने में ये माहिर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन अपनी दृढ़इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है तो उसे कभी मानवीयता का पाठ पढ़ाया जाता है तो कभी उच्च न्यायिक आदर्शों व प्रतिमानों का। क्योंकि हरेक मुद्दे को लेकर ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि समान पृष्ठभूमि वाले मुद्दों/मामलों में इनकी भूमिका और विचार अलग अलग देखे जाते हैं, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए जैसे को तैसा की तर्ज पर यदि प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तो सत्ता संरक्षित अपराध करने वालों, नक्सलियों-आतंकियों-अंडरवर्ल्ड के स्लीपर सेल के रूप में काम करने वालों, इसकी आड़ में तस्करी, फिरौती का धंधा करने वालों को नियंत्रित करना मुश्किल होगा।

आप मानें या न मानें, लेकिन यूपी की सुधरती कानून व्यवस्था के पीछे पुलिस एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर न्याय का बहुत बड़ा हाथ है। अब अपराधियों के मन में दहशत है कि यदि गलत किये तो जान भी जा सकती है और घर भी। चूंकि सबको अपने परिवार से प्रेम रहता है, इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि उसकी करतूतों से उसका परिवार सड़क पर आ जाए। लेकिन हत्याओं और दंगों को रोकने और पीड़ितों को त्वरित न्याय देने/दिलवाने में विफल भारतीय न्यायिक व्यवस्था अब जिस तरह से पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर न्याय पर दिशा निर्देश दे रही है, उससे वह कार्यपालिका हतोत्साहित होगी, जिसने बेहतर परिणाम दिए हैं। यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कार्रवाई हुई है और इसे बंद करने के आपराधिक दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

वहीं, इस अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका के हाथ सिर्फ इसलिए बांधे रखना चाहती है कि सम्बन्धित विषय उसके समक्ष न्याय के लिए उठाया गया है, लिहाजा वह न्याय देने की प्रक्रिया में सम्बन्धित विषयों/निर्णयों के तमाम व्यवहारिक पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ आदर्शवादी फैसले दे देती है। इससे जहां कुटिल सियासतदानों और खल प्रवृत्ति वाले समाजसेवियों के हौसले बढ़ते हैं।

सीधा सवाल है कि जब किसी व्यक्ति की हत्या करने के वक्त या सामाजिक दंगा-फसाद करने के वक्त अपराधी कुछ नहीं सोचते और भारी जानमाल की क्षति कर जाते हैं, तो फिर उनपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक पल का भी इंतजार क्यों? बेहतर तो यह होता कि वहीं पर मोबाइल कोर्ट बैठती और तुरंत आदेश जारी करती कि ऐसे दोषियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें तुरंत शूट आउट किया जाए। इसके संरक्षकों की पहचान की जाए और उसे भी कठोर सजा मिले। भारत में अपराध को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमन की गंगा-यमुना में बहुत पानी बह चुका है।

मेरी स्पष्ट राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते बुलडोजर न्याय पर जो रोक लगा दी है, उस पर पुनर्विचार करे। भले ही अदालत ने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को बिना मुकदमा चलाए सजा देना अनुचित है, लेकिन वह खुद शोध करके बताए कि हिंसा को रोकने में पिछले सात दशक की उसकी उपलब्धि क्या है? भारत के आमलोग तरह-तरह की हिंसा-प्रतिहिंसा झेलते रहे, प्रशासन तमाशबीन और मूकदर्शक बना रहा और न्यायपालिका भी खामोश रही! क्या वह तमाम समाचारों से नावाकिफ रहती है? उसे त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए कि हत्या और दंगा जैसे जघन्य अपराध पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसे मामलों में सख्त सजा देने में एक सप्ताह का समय भी काफी अधिक होता है। हमारी न्यायपालिका यह कैसे कर पाएगी, उसके उपाय ढूंढे और वित्त की कमी का रोना न रोए।

कहना न होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर जो प्रभावी रोक लगाई है, वह अपराधियों पर नियंत्रण का एक साधन बनती जा रही थी, लेकिन अब इसे कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ माना गया है। इससे अपराधियों के हौसले फिर बढ़ेंगे। भले ही देश के अलग-अलग हिस्सों में शुरू हुए 'बुलडोजर न्याय' के नए चलन में निहित खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रभावी रोक लगा दी है, लेकिन इस रोक के श्वेत और श्याम पक्ष को देख लिया गया होता तो बेहतर होता। इस संबंध में आया सर्वोच्च अदालत का फैसला निश्चित रूप से सख्त फैसलों की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन यह सख्ती कितनी जरूरी थी, यह वक्त बताएगा। आपराधिक आंकड़े चुगली करेंगे।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

क्या हम आशा करें कि वेदानुयायी होने का दावा करने वाले सज्जन अपने पुराण-विषयक अम को दूर करके पुराणों की उपयोगिता स्वीकार करेंगे ।

मन्त्र से पूर्व नियम विनियोग, (छन्द ऋषि देव-ज्ञान विनियोग।) देव-ऋषि-चरित-कोश सुपुराण, यही अध्याय तीसरा जान।।

पूर्वोक्त रीति से जब वेदादि प्रमाणों की प्राचीनता सिद्ध हो जाया करती है तो घबड़ाकर प्रतिवादी कह दिया करते हैं कि निर्दिष्ट प्रमाणों में पुराण नाम ब्राह्मण ग्रन्थों का है- वर्तमान पुराणों का नहीं । अत: इस अध्याय में इसी बात पर विचार किया जायगा कि क्या वास्तव में ब्राह्मण-ग्रन्थों को पुराण कहते हैं, अथवा वर्तमान उपलब्ध 18 पुराणों को ही पुराण कहना चाहिये ?

(1) सब से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि प्रतिवादी का यह कथल कि-पुराण% नाम ब्राह्मण ग्रन्थों का है, और वेदादि सच्छास्त्रों में उन्हीं का नाम आया है-निरा भ्रम है, क्योंकि इस कथन से वर्तमान पुराणों की नवीनता तो सिद्ध होनी दुरूह है परन्तु प्रतिवादी, जिन वेदों को अनादि मानता है और जो वास्तव में हैं भी अनादि, वह कल के बने जरूर सिद्ध हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि यदि दुर्जन-तोष-न्याय से क्षण मात्र के लिए मान लिया जाए कि ब्राह्मण-ग्रन्थ ही पुराण हैं तो जिस मन्त्र में धड़ाधड़ उक्त पुराणों का नाम आ रहा है वह मन्त्रभाग ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद का बना मानना पड़ेगा । जबकि प्रतिवादी ब्राह्मण ग्रन्थों को महाभारत संग्राम के पश्चात् बने मानता है तो मन्त्र भाग को और भी पीछे का बना मानना पड़ेगा । क्या कोई बुद्धिमान् यह स्वीकार करने को प्रस्तुत होगा कि वेद 5000 वर्ष से भी इधर के हैं? शायद इस आपत्ति को समझ कर प्रतिवादी भी स्वयं अपने पाँवों पर कुल्हाड़ा मारने को उद्यत न होगा **(क्रमशः)**

लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की नाक में कर दिया था दम

अनन्या मिश्रा

भारत मां को वीर सपूतों की जननी कहा जाता है। इन वीर सपूतों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे में ही एक स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब भी कहा जाता है। देश को आजादी दिलाने के साथ ही लाला लाजपत राय मे लक्ष्मी बीमा कंपनी और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल-बाल-पाल में से एक थे।

पंजाब के फिरोजपुर में 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आजाद था और वह फारसी और उर्दु के महान विद्वान थे।

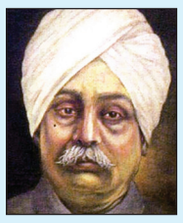

आपको बता दें कि साल 1897 और 1899 में देश में अकाल पड़ गया था। इस दौरान लाला लाजपत राय ने तन, मन और धन से पीड़ितों की सेवा की थी। जब देश में भूकंप और अकाल के दौरान ब्रिटिश शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से अनेकों जगहों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। वहीं साल 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिनचंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया।

लाल-बाल और पाल की इस तिकड़ी को जनता का समर्थन मिल रहा था। साथ ही इस तिकड़ी ने देश को आजाद कराने के लिए जो नए-नए प्रयोग किए थे वह सब अपने आप में नायाब थे। वहीं लाल-बाल और पाल की इस तिकड़ी ने अंग्रेजों के रात की नींद हराम कर दी थी। वहीं साल 1917 में लाला लाजपत राय अमेरिका पहुंचे। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की थी।

इस संगठन के जरिए वह लगातार स्वाधीनता की चिंगारी को हवा देते रहे। जब तीन साल बाद साल 1920 को लाला लाजपत राय भारत वापस लौटे, तब तक वह भारतीयों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पंजाब में उग्र प्रदर्शन किया। वहीं जब साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा तो लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई।

जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो लालाजी भी अन्य विरोधियों के साथ इस कमीशन का विरोध करने लगे। क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था। इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़े जनसैलाब को देखकर ब्रिटिश सेना बुरी तरह से बौखला उठी। लाठी चार्ज में बुरी तरह से घायल हुए लाजपत राय का स्वास्थ्य धीरे-धीरे बिगड़ने लगा। वहीं 17 नवंबर 1928 को भारत मां के इस वीर सपूत ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह का अपमान क्यों?

बलबीर पुंज

बीते दिनों पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने यह कहते हुए शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह को समर्पित करने की वर्षों पुरानी मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं, बल्कि 'अपराधी' और आज की परिभाषा में 'आतंकवादी' थे। मुझे पाकिस्तान की इस हिमाकत पर कोई हैरानी नहीं हुई। क्या इस इस्लामी देश से किसी अन्य व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है?

लाहौर में जिस स्थान पर 23 मार्च, 1931 को महान स्वतंत्रता सेनानियों- भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, वह जगह शादमान चौक के नाम से प्रसिद्ध है। इसी मामले में 8 नवंबर को लाहौर उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। तब 'भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन पाकिस्तान' द्वारा अदालत में दायर एक याचिका पर लाहौर प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा, 'शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा लगाने की प्रस्तावित योजना को पूर्व नौसेना अधिकारी तारिक मजीद की टिप्पणी के आलोक में रद्द कर दिया गया है।' मजीद मामले में गठित समिति का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा था कि भगत सिंह ने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, इसलिए उन्हें 2 साथियों के साथ फांसी दे दी गई थी।

इसी समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भगत सिंह 'मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण मजहबी नेताओं से प्रभावित थे और भगत सिंह फाऊंडेशन इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा था, (और) इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।' बकौल रिपोर्ट, 'फाऊंडेशन के अधिकारी, जो खुद को मुस्लिम कहते हैं, क्या वे नहीं जानते कि पाकिस्तान में किसी नास्तिक के नाम

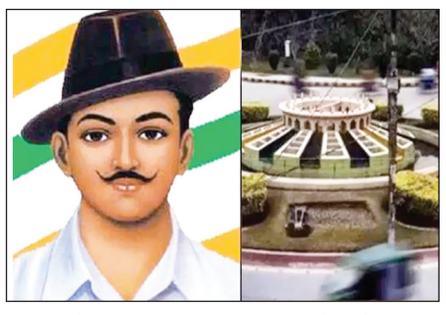

पर किसी जगह का नाम रखना अस्वीकार्य है और इस्लाम में मानव मूर्तियां प्रतिबंधित हैं?' मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी।

पाकिस्तान में भगत सिंह का रिश्ता केवल लाहौर जेल तक सीमित नहीं है। जिस अविभाजित पंजाब के लायलपुर में उनका जन्म हुआ था, वह भी अब पाकिस्तान में है। लाहौर के ही नैशनल कॉलेज में भगत सिंह के अंदर क्रांति के बीज फूटे थे और 'नौजवान भारत सभा' का गठन भी लाहौर में किया गया था। यदि इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान भगत सिंह को अपना 'नायक' मान लेता, तो ऐसा करके वह अपने वैचारिक अस्तित्व, जिसे 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरणा मिलती है, उसे प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से नकार देता। पाकिस्तानी सत्ता-वैचारिक अधिष्ठान के लिए भगत सिंह भी एक 'काफिर' हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इस जहरीले ड्क्षचतन की जड़ें बहुत गहरी हैं। गांधीजी ने अली बंधुओं (मौलाना मुहम्मद अली जौहर और शौकत अली) के साथ मिलकर विदेशी खिलाफत आंदोलन (1919-24) का नेतृत्व किया था। परंतु मौलाना मुहम्मद अली जौहर स्वयं गांधीजी के बारे में क्या सोचते थे, यह उनके इस विचार से स्पष्ट है- 'गांधी का चरित्र चाहे कितना भी शुद्ध क्यों न हो, मजहब की दृष्टि से वे मुझे किसी भी चरित्रहीन मुसलमान से हीन प्रतीत होते हैं।'

बात यदि वर्तमान पाकिस्तान की करें, तो वह विभाजन के बाद अपने दस्तावेजों, स्कूली पाठ्यक्रमों और अपनी आधिकारिक वैबसाइटों में इस बात का उल्लेख करता आया है कि उसकी जड़ें सन् 711-12 में इस्लामी आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम द्वारा हिंदू राजा दाहिर द्वारा शासित तत्कालीन सिंध पर किए हमले में मिलती हैं। इसमें कासिम को 'पहला पाकिस्तानी', तो सिंध को दक्षिण एशिया का पहला 'इस्लामी प्रांत' बताया गया है। जिन भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनाया गया था, वहां हजारों वर्ष पहले वेदों की ऋचाएं सृजित हुईं थीं और बहुलतावादी सनातन संस्कृति का विकास हुआ था। इसलिए पुरातत्वविदों की खुदाई में वहां आज भी वैदिक सभ्यता के प्रतीक उभर आते हैं, जिनका इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। परंतु पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के नाम पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी, आर्य सभ्यता, कौटिल्य और गांधार कला से जुड़ने का प्रयास करता है। इसी वर्ष 29 मई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, 'पाकिस्तान को अपनी प्राचीन बौद्ध विरासत पर गर्व है।'

वास्तव में, यह क्रूरतम मजाक है। जिन इस्लामी आक्रांताओं कासिम, गजनवी, गौरी, बाबर, टीपू सुल्तान आदि को पाकिस्तान अपना घोषित 'नायक' मानता है, जिनके नामों पर उसने अपनी मिसाइलों-युद्धपोतों का नाम रखा है, उन्होंने ही 'काफिर-कुफ्र अवधारणा से प्रेरित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में गैर-इस्लामी प्रतीकों (हिंदू-बौद्ध सहित) का विनाश किया था। इस चिंतन में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। जब जुलाई 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में निर्माण कार्य के दौरान जमीन से भगवान गौतम बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा मिली थी, तब स्थानीय मौलवी द्वारा इसे गैर-इस्लामी बताने पर लोगों ने मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया था।

पाकिस्तानी कौमी तराना (राष्ट्रगान) का मामला और भी दिलचस्प है। वर्ष 1947 में इस्लाम के नाम पर खूनी विभाजन के बाद शेष विश्व के सामने पाकिस्तान को तथाकथित 'सैकुलर' दिखाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मूल के उर्दू शायर जगन्नाथ आजाद द्वारा लिखित एक उर्दू गीत को राष्ट्रगान बनाया था। जिन्ना की मृत्योपरांत लगभग डेढ़ वर्ष तक यह पाकिस्तान का राष्ट्रगान रहा। चूंकि इसे 'काफिर' हिंदू ने लिखा था, इसलिए इसका पाकिस्तानी नेतृत्व से लेकर आम लोगों ने भारी विरोध किया और इसपर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1952 में हाफिज जालंधर द्वारा फारसी भाषा में लिखित गीत को कौमी-तराना बनाना मुकर्रर हुआ। यह स्थिति तब है, जब इस इस्लामी देश की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा उर्दू-अंग्रेजी है और यहां पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, सराइकी इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इसका राष्ट्रगान उस फारसी भाषा में है, जिसे बोलने/समझने वालों की संख्या पाकिस्तान में बेहद सीमित है।

पाकिस्तान में यह हड़बड़ाहट उसके वैचारिक अधिष्ठान के कारण है, जो पिछले 77 वर्षों से अपनी पहचान भारत में जनित और विकसित सांस्कृतिक जड़ों से काटने और मध्यपूर्व-अरब देशों से जोडने का असफल प्रयास कर रहा है। इसलिए इस जड़-विहीन पाकिस्तान को उसके इस्लामी होने के बावजूद मध्यपूर्वीय देश सम्मान या बराबर की नजर से नहीं देखते। पाकिस्तान में एक बड़े भाग द्वारा शहीद भगत सिंह का विरोध भी अपनी मूल जड़ों को नकारने की विचारधारा से ही प्रेरित है।

आज का इतिहास

1944 द्वितीय ब्रिटिश सेना ने वासेम पर कब्जा कर लिया।
1950 15 वर्षीय तेनजिग ग्यात्सो, 14वें दलाई लामा बने।
1950 तेनज़िन ग्यात्सो, 14 वें दलाई लामा, पंद्रह साल की उम्र में तिब्बत के राज्य मंत्री के रूप में आकर्षित हुए थे।
1953 इतालवी स्टीमर, विटोरिया क्लाउडिया और फ्रांसीसी अयस्क वाहक के बीच टक्कर, द पेरोइन द इंग्लिश चैनल विटोरिया क्लाउडिया को 20 इतालवी सीमेन की मौत की ओर ले जाता है।
1968 एनबीसी ने विवादास्पद रूप से अमेरिकी फुटबॉल गेमबेटन को ओकलैंड रेडर्स और न्यूयॉर्क जेट्स से दूर कर दिया और हेदी को प्रसारित करने के लिए, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्शकों को गेम के नाटकीय अंत को देखने से इनकार कर दिया।
1970 सोवियत संघ का चंद्रमा रोवर, पहला रोसिंग रिमोट-नियंत्रित रोबोट ने लैंडिंग किया और आज चंद्रमा की सतह पर लुढ़का, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला रोबोट बना।
1970 अमेरिकी आविष्कारक डगलस एंगेलबार्ट को thefirst कंप्यूटर माउस के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ।
1993 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) को मंजूरी दी।
1993 जनरल सानी अबचा ने अर्नेस्ट शोनकान को नाइजीरिया की अनंतिम शासक परिषद का अध्यक्ष बनाया।
1997 दक्षिणी मिस्र में 68 विदेशी सैलानी तब मारे गए जब चरमपंथियों ने सैलानियों की बस पर हमला किया।
2000 अलबर्टो फुजिमोरी को पेरू के राष्ट्रपति के पद से हटाया गया।
2002 पेनकेन से लैस एक अपहर्ता ने इज़राइल से इस्तांबुल, तुर्की जाने वाले एक विमान को अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि घटनाओं के एक मोड़ में उसे पकड़ लिया गया और विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया।
2005 यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा बहस योग्य रासायनिक सुरक्षा का एक आइटम पारित किया गया है। यह पंजीकरण, मूल्यांकन और प्राधिकार के रसायन कानून के रूप में जाना जाता है।
2006 प्ले स्टेशन 3, सोनी का नया कंसोल उत्तरी अमेरिका में 14 लॉन्च टाइटल्स के साथ जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान गर्माया

राहिल नोरा चोपड़ा

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ गया है क्योंकि राज्य में 9 विधानसभा सीटों के लिए आगामी उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव के लिए दाव बहुत ऊंचे हैं।

एक ओर, सपा ने पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक (पी.डी.ए.) रणनीति के माध्यम से जातिगत विविधता पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, जो पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच एकता पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण इसके उम्मीदवारों की सूची में भी झलकता है- 2 दलित, 4 मुस्लिम और 3 अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) के उम्मीदवार।

जबकि योगी ने बंगलादेश में हिंदुओं पर हमलों के संबंध में 'बंटेंगे तो कटेंगे' के कट्टरपंथी नारे के साथ हिंदुत्व के एजैंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया, जिसका अर्थ है कि वोटों का विभाजन चुनावों में विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, भाजपा मतदाताओं का दिल जीतने के लिए आदित्यनाथ के शासन के दौरान 'सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था' का प्रचार कर रही है। इस बीच, मायावती की बसपा चुपचाप नहीं बैठी है, उसने सभी 9 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे उप-चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। बसपा के यू.पी. अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने प्रचार की कमान संभाली है, हालांकि मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद खास तौर पर अनुपस्थित रहे हैं।वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव न लडने और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। सपा की जीत राज्य में भाजपा के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उसके दावे को मजबूत करती है। इससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर सपा की स्थिति भी मजबूत होगी। भाजपा की जीत से आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर आलोचनाओं से निपटने में मदद मिलेगी।

नवगठित 15वीं हरियाणा विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र 13 नवम्बर, 2024 को शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने विधायक दल (सी.एल.पी.) के नेता की घोषणा नहीं की है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का राजनीतिक मौका मिल गया है। सी.एल.पी. नेता चुनने में देरी और इंतजार ने एक बार फिर पार्टी की राज्य इकाई में आंतरिक गुटबाजी को उजागर कर दिया है, जिसे पार्टी बार-बार छिपाती और नकारती रही है। हुड्डा और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा के खेमों के बीच पार्टी में विभाजन चुनावों के दौरान स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले सदन में विपक्ष के

नेता थे। हालांकि, चुनाव नतीजों के एक महीने बाद भी पार्टी अपना विधायक दल का नेता चुनने में विफल रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्हें 20 नवम्बर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के बाद ही घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, कांग्रेस आलाकमान हुड्डा का नाम घोषित करने और उन्हें सी.एल.पी. नेता के रूप में जारी रखने के लिए उत्सुक नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही, एन.सी.पी. नेताओं के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा के अभियान के 'बंटेंगे तो कटेंगे' नारे पर अपनी बेचैनी को उजागर किया है और सत्तारूढ़ गठबंधन के सत्ता में लौटने पर शासन के लिए एक सांझा न्यूनतम कार्यक्रम का आह्वान भी किया है। वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एन.सी.पी. (शरद पवार गुट) और कांग्रेस से मिलकर बने एम.वी.ए. ने 'लोकसेवा पंचसूत्री' के तहत कई तरह के वादे किए हैं। इसमें 3,000 रुपए प्रति माह का प्रत्यक्ष नकद लाभ और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। गठबंधन ने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने और ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 50,000 रुपए देने का भी वादा किया है।

उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का 'लाभ' देने और गरीबों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का भी वादा किया है। भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है, पिछले कुछ समय से नकद सहायता दे रहा है। लेकिन एम.वी.ए. के वादों के दबाव में, महायुति ने अपनी 'लाडकी बहिन योजना' की पेशकश को महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति माह कर दिया है, साथ ही छात्रों को 10,000 रुपए प्रति माह सहायता और किसानों को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी है, जो पहले 12,000 रुपए थी।

अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 3 महीने बचे हैं, ऐसे में 'आप', भाजपा और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपने-अपने संपर्क कार्यक्रम शुरू करके चुनावी माहौल में कमर कस ली है। कांग्रेस नेता और 5 बार के विधायक मतीन अहमद आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए, जबकि दिल्ली के पूर्व मंत्री हरशरण सिंह बल्ली सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। शराब 'घोटाले' को उछालकर, भाजपा को उम्मीद है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा के रूप में केजरीवाल की छवि को सफलतापूर्वक धूमिल कर देगी। हालांकि, 'आप' को उम्मीद है कि जांच में कम प्रगति और धीमी अदालती कार्रवाई के साथ, व्यक्तिगत दुराचार के आरोपी सत्येंद्र जैन सहित सभी गिरफ्तार 'आप' नेताओं को जमानत मिलने के साथ, भाजपा की रणनीति को जांच एजैंसियों के दुरुपयोग के रूप में देखा जाएगा।

विदर्भ की 62 में 36 सीटों पर कांग्रेस-भाजपा में सीधा मुकाबला

सुरेन्द्र मिश्र

महाराष्ट्र के विदर्भ में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) लोकसभा चुनाव के नतीजे दोहराने की फिराक में है। वहीं, सत्तारूढ गठबंधन महायुति विशेष तौर से भाजपा, 2014 जैसी सफलता पाने के लिए संघर्षरत है। विदर्भ की 62 सीटों पर कांटे की लड़ाई है, जहां आघाड़ी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी संविधान बचाओ के नारे और जातिगत समीकरण के सहारे है। वहीं, भाजपा के सामने विदर्भ का गढ़ बचाने की चुनौती है। इसलिए भाजपा ने बंटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे का नारा दिया है। कांग्रेस इन्हीं नारों की काट में उलझी है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। दो धुर विरोधी विचारधारा की पार्टी कांग्रेस और भाजपा विदर्भ पर कब्जे के लिए संघर्ष कर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा अब एकजुटता का राजनीतिक संदेश दे रही है, क्योंकि इस बार वोटकटवा का लाभ मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसके अलावा, लाडकी बहना जैसी लोकलुभावन योजनाओं के जरिए भी जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश है। वहीं, कांग्रेस को भरोसा है कि विदर्भ उनका गढ़ रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति विधानसभा में भी होगी। भले ही संविधान बचाओ का नारा विधानसभा चुनाव में प्रभावी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जातीय समीकरण उसके पक्ष में है। उसने सोयाबीन और कच्चे कपास के उचित मूल्य को भी मुद्दा बनाया है, लेकिन, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि सीट बंटवारे में विदर्भ में वह 40 से अधिक सीटें हासिल नहीं कर पाई है। भाजपा नेता अजय पाठक कहते हैं कि पिछले चुनाव से इस बार काफी कुछ बदल गया है। विदर्भ में भाजपा 2014 में जीती गई 44 सीटों की बराबरी करेगी। कांग्रेस नेता व नागपुर उत्तर से उम्मीदवार नितिन राउत कहते हैं कि कृषि उपज के अलावा महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी भी एमवीए का चुनावी मुद्दा है। विदर्भ में एमवीए बेहतर प्रदर्शन करेगी। साल 2014 में मोदी लहर में विदर्भ से ही पहली बार महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता का द्वार खुला था। इस बार भी यही माना जा रहा है कि मुंबई की ओर जाने वाला सत्ता का गलियारा विदर्भ से होकर गुजरेगा। इसलिए दोनो ही गठबंधन ने विदर्भ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में तीन-तीन राजनीतिक दलों का समूह भाजपानीत महायुति और कांग्रेसनीत एमवीए के रूप में एक-दूसरे के सामने मैदान में हैं। विदर्भ के 11 जिलों की बात करें, तो यहां महायुति की भाजपा और एमवीए के मुख्य दल कांग्रेस के बीच ही चुनावी टक्कर है। यहां की 62 विधानसभा क्षेत्रों में 36 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। शिवसेना (उद्धव गुट) बनाम शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच छह सीटों पर और एनसीपी (शरद गुट) बनाम एनसीपी (अजीत गुट) के बीच सात सीटों पर सीधी लड़ाई है। हालांकि एनसीपी (अजीत गुट) में तीन उम्मीदवार भाजपा से आयातित हैं। भाजपा के कुछ प्रमुख नेता विदर्भ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी, सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह से और मदन येरावर यवतमाल से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साकोली (भंडारा) व विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी से मैदान में हैं।

बार-बार चुनाव लोकतंत्र की तौहीन

प्रो. दरबारी लाल

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं गौरवमयी प्रजातांत्रिक पद्धति सम्पन्न राष्ट्र है। पवित्र संविधान के लागू होने के पश्चात पहली बार 1952 में चुनाव आजादाना गैर-जानिबदाराना और अमनो-अमान के साथ 5 महीनों में पूरे हुए। भारतीयों के लिए यह चुनाव सबसे बड़ा उत्सव था क्योंकि पहली बार इतिहास में मजहबों मिल्लत, अमीर और गरीब के भेदभाव कों दर-किनार करके सबको समान मतदान करने का अधिकार मिला था। लोग कई मील पैदल चल कर, बैलगाडियों में बैठ कर तथा कई ढोल-बाजों के साथ काफी संख्या में इकट्ठे होकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे थे। देश में पहली बार केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे।

हकीकत में यहीं से एक राष्ट्र एक चुनाव की सुनहरी परम्परा शुरू हुई थी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और सुविख्यात स्टेट्समैन पंडित नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात 1957, 1962, 1967 में संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे और राष्ट्र विकास के पथ पर बिना रुकावट चलता रहा। 1967 के चुनाव में केन्द्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तासीन हो गई परंतु तमिलनाडु समेत 9 राज्यों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इन राज्यों में छोटे-बड़े दलों ने मिलकर संयुक्त सरकारें बनाईं जिन्हें मजाक में खिचड़ी सरकारें भी कहते थे। इन सरकारों की न तो एक नीति थी, न एक विचारधारा और न ही विकास का कोई सुनियोजित और सुनिश्चित प्रोग्राम। हकीकत में यह भानुमती का कुनबा था। इस तरह पहली बार कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला हो गया। इस बड़े राजनीतिक परिवर्तन के कई कारण थे। प्रथम 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1965 में भारत-पाक युद्ध, देश में अनाज की कमी से बढ़ती हुई महंगाई तथा राष्ट्र के 2 अति लोकप्रिय महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का दुनिया से रुखस्त हो जाना।

राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। तमिलनाडु में डॉक्षहदी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन ने जोर पकड़ा। कई प्रदेशों में बेकारी के कारण नौजवान सड़कों पर उतर आए।

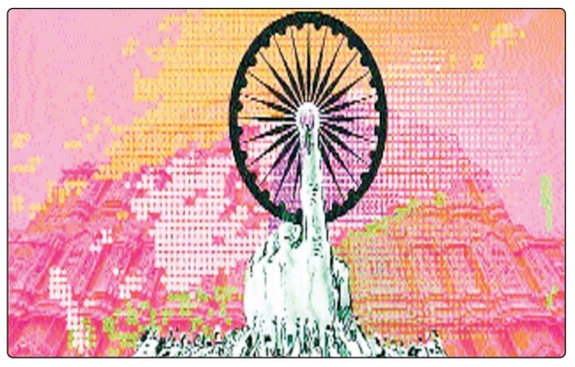

कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगने लगे जिसके परिणामस्वरूप प्रदेशों में गैर-कांग्रेस सरकारें अस्तित्व में आ गईं परंतु किसी का कार्यकाल 8 महीने, किसी का 9 महीने कोई एक साल बाद दम तोड़ गया। इस तरह राज्यों में चुनाव पर चुनाव होने लगे जो आज भी लगातार जारी है। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हर वर्ष 3 से 5 राज्यों में चुनाव होने लगे जिससे एकरूपता, एकसारता और एकजुटता की कडियों में बिखराव आ गया।

केन्द्र में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद निश्चित समय के एक साल पहले चुनाव करवा दिया। इस तरह केंद्र में भी गठजोड़ सरकारें बनती, टूटती गईं और फिर कई बार नए चुनाव करवाने पड़े। हकीकत में 1967 से लेकर आज तक केंद्र और राज्यों में एक समय पर चुनाव करवाने की सुनहरी परम्परा पटरी से उतर गई। अब हर वर्ष कई प्रदेशों में चुनाव होते रहते हैं।

केंद्र में बार-बार सरकारों का बदलना और प्रदेशों में सरकारों के बनने और टूटने से देश की समूची राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और समाज पर बुरे प्रभाव पडने लगे। संयुक्त सरकारों के समय देश में भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो गया जो आज तक समूचे समाज में कैंसर की तरह गहरी जड़ें पकड़ता जा रहा है। ईमानदार, दयानतदार, बेदाग और योग्य नेताओं के स्थान पर कई अपराधी तत्वों का राजनीति में बोलबाला हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था अक्षमता की तरफ बढने लगी और छोटे-छोटे काम करवाने के लिए लोगों को रिश्वत के साथ-साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।

प्रशासन में अनावश्यक दखलअंदाजी से कानून-व्यवस्था भी बिगडने लगी। विकास के कार्य भी धीमे होने लगे। प्रजातंत्र 'अमीरों की बांधी' का रूप धारण करने लगा। बार-बार चुनावों में वोट हासिल करने के लिए राजनेताओं ने विकास के स्थान पर मुफ्तखोरी का प्रलोभन देना शुरू कर दिया जबकि ऐतिहासिक हकीकत यह है कि मुफ्तखोरी से लोगों में संघर्ष करने की भावना कम होने लगती है और आलस की नई बीमारी जन्म ले लेती है। बार-बार चुनावों से राजनीतिक दलों में गैर-जरूरी तनाव पैदा होने लगता है। वेनेजुएला और श्रीलंका की जबरदस्त बर्बादी इस मुफ्तखोरी के कारण हुई। 2024 के संसदीय चुनाव में एक अरब 35 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह केवल सरकारी खर्च है, इसके अतिरिक्त संसदीय उम्मीदवारों ने कितना खर्च किया यह हिसाब से ही बाहर है। हर वर्ष यदि 3 से 5 राज्यों में चुनाव किए जाएं तो उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च होता है जो लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ है।

यदि 5 वर्षों में एक बार केंद्र और राज्यों के चुनाव करवा दिए जाएं तो धन भी कम खर्च होगा और बचे हुए धन से विकास के कार्यों को खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। बार-बार चुनावों से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश की सरकारों और पड़ोसी राज्यों के नेताओं की सारी शक्ति चुनाव जीतने में लग जाती है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता आ जाती है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के साथ एक ही मतदाता सूची भी होनी चाहिए ताकि पंचायतों, नगर कौंसिलों, निगमों, विधानसभाओं और संसदीय चुनावों में वोट डालते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चुनावों के लिए 5 वर्षों में 3 महीने निश्चित कर दिए जाएं ताकि शेष समय में सरकारें राष्ट्र के विकास की तरफ ध्यान दे सकें और इससे रोज-रोज की अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी खत्म हो जाएगा। एक राष्ट्र-एक चुनाव के विरोधियों के लिए 2 पंक्तियां अर्ज करता हूं- बार-बार चुनाव हकीकत में जम्हूरियत की तौहीन है। एक राष्ट्र एक चुनाव में ही सबका यकीं है।

'वोट' बंटेंगे या कटेंगे या फिर रहेंगे 'सेफ'?

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चरम दौर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का अपनी वर्तमान पार्टी के नारे से स्वयं को अलग करना अनेक प्रकार के आश्चर्य को जन्म देता है। यही नहीं पार्टी की एक अन्य वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य पंकजा मुंडे का भी पार्टी के नारे के प्रति असहमति जताना विचार योग्य तथ्य है। यह सब उस दौर में हो रहा है, जब राज्य की महाविकास आघाड़ी और महागठबंधन दोनों के डेढ़ सौ से अधिक बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

छह पार्टियों के बीच होने वाले मुकाबलों में पहले टूटे और मूल दलों के बीच ही मुकाबलों की स्थितियां बनी हैं। उसके बाद उन्हीं के अपने बागी नेता अलग परेशानी का कारण बने हैं। इस परिस्थिति में मतों का बिखराव और मतदाता के लिए निर्णय लेने की जटिल परिस्थिति उभर कर सामने है, जिससे निपटने से ही राज्य के चुनाव परिणाम निर्धारित होंगे।

मगर वर्ष 1995 के बाद राज्य की राजनीति सबसे अधिक चिंताजनक और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। राज्य में वर्ष 1995 के चुनाव में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों शरद पवार और सुधाकरराव नाईक के बीच टशन बढ़ने से कांग्रेस के दो गुट बने और जहां दोनों से उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, वहां से उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बना कर चुनाव मैदान में उतार दिया गया था।

उस चुनाव में सभी प्रकार के प्रत्याशियों सहित 3196 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 45 चुनाव जीत भी गए थे। इसी बगावत ने पहली बार भाजपा और शिवसेना की सत्ता पाने की राह आसान कर दी थी। इससे पहले, वर्ष 1990 के चुनाव में भी 13 बागी जीते थे। शिवसेना ने वर्ष 1995 में 169 में से 73 सीटें, जबकि भाजपा ने 116 में से 65 सीटें जीती थीं।

दोनों पार्टियों की सीटों में शिवसेना की 21 और भाजपा की 23 सीटों की बढ़ोत्तरी हुई थी। मगर दोनों बहुमत से पीछे रह गए थे, जिसके बाद 45 निर्वाचित निर्दलीयों में से 14 की मदद से राज्य

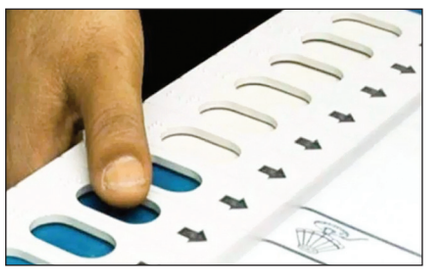

में पहली बार गैर-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनी थी। अतीत के आलोक में इस बार चुनाव में राज्य में कुल चार हजार 140 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2086 निर्दलीय हैं।

यह माना जा रहा है कि निर्दलीयों में डेढ़ सौ से अधिक अलग-अलग दलों के बागी उम्मीदवार हैं। इस स्थिति के बाद अनेक छोटे दलों से बेहतर स्थिति में निर्दलीय माने जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कम से कम 25-30 निर्दलीय जीतने की स्थिति में हैं। वर्ष 1995 के चुनाव के सापेक्ष देखा जाए तो उस समय कांग्रेस को 286 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 61 सीटें घटने का झटका लगा था, तब उसे केवल 80 सीटें ही मिली थीं। ताजा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी यदि नहीं भी है तो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) का विभाजन कोई कम नहीं है।

यदि उस समय कांग्रेस के अंदर-बाहर की बात थी तो इस बार पहले आमने-सामने का मुकाबला करते हुए अपनी पार्टी को भीतर से भी संभालना है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के नेताओं के हौसले बुलंद हुए, उसी तरह महत्वाकांक्षी नेताओं के इरादे भी समझ में आने लगे थे।

अक्सर समझाने के लिए हर दल में कहा जाता है कि पार्टी को चलाने के लिए उसके निर्णयों को मानना आवश्यक होता है। यह भी बताया जाता है कि किसी सीट पर टिकट पाने के लिए नामों की सूची लंबी होती है, किंतु टिकट एक को ही मिल पाता है। बावजूद इन सैद्धांतिक बातों के, अनेक नेताओं को साल-महीने पहले से चुनाव की तैयारी कराई जाती है।

उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन चुनाव की बात आने पर वरिष्ठ नेता या आलाकमान के निर्णय को सर्वोच्च मानकर बगावत की आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है। यहीं से पार्टी परिणामों के संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं। ताजा परिस्थितियों में महाविकास आघाड़ी से लेकर महागठबंधन तक अपनों से ही मुकाबला करने में समय दे रहा और परिश्रम कर रहा है।

यह तय है कि राज्य में व्यापक स्तर पर मत विभाजन होगा। परिणाम कहीं अपेक्षा अनुरूप तो कहीं बिल्कुल विपरीत सामने आ सकते हैं। राज्य में आम तौर पर चार से पांच उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की स्थितियां बन रही हैं। जहां-जहां प्रदेश के दोनों गठबंधन आपस में मुकाबला कर रहे हैं, वहां वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

गौरतलब है कि राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अधिक 237 उम्मीदवार और उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी ने 200 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा सभी बड़े दलों के बागी नेता भी निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि लगभग डेढ़ सौ से अधिक सीटों पर अच्छी-खासी संख्या में मत विभाजन होगा, जो सभी गठबंधनों को प्रभावित करेगा।

वोट बंटने के बाद वोट कटने की बारी आएगी और जो इन दोनों से बच जाएगा वह अपने आप 'सेफ' हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में विचारधारा के परे आरंभ हुई राजनीति ने स्वतंत्र नेताओं के लिए नई राह खोल दी है। पार्टी छोड़ना और लौटना कोई असामान्य घटना नहीं रह गई है। इस चुनाव में अनेक नेताओं को टिकट न मिलने की स्थिति में दूसरी पार्टी में भेजकर टिकट दिलवाया गया।

इस स्थिति में केवल मतदाता से बंटने और कटने या फिर एक और 'सेफ' की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जब राजनीतिक दल टुकड़ों-टुकड़ों में अपना अस्तित्व बना कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो मतदाता से कैसे अपेक्षा की जाए कि वह एकजुटता के साथ उनका साथ दे। फिलहाल यह राजनीति का नया दौर है। इसके परिणामों से ही अगली दिशा तय होगी और पता लगेगा कि कौन बंटा, किसने काटा और कैसे कोई 'सेफ' रह पाया।

इसे 'फ्रीबीज' या रेवड़ी मत कहिए

अरविंद मोहन

अभी तक इंगलिश शब्द फ्रीबीज का अनुवाद कहीं खैरात नजर नहीं आया है। (खैरात खाने या लेने को बुरा माना जाता है। पहले तो बहुत बुरा माना जाता था और अब भी माना जाता है।) इसमें खैरात देने वाले को पुण्य मिलने और खाने वाले को उसके पापों में हिस्सेदारी आ जाने का भाव माना जाता है। चुनाव के समय दिए जाने वाली लोक-लुभावन सरकारी खैरातें या सरकार बनने पर दिए जाने वाले लाभों के वायदे को अंग्रेजी में फ्रीबीज कहा जाता है और मीडिया ने उसके अर्थ के काफी आसपास का शब्द रेवड़ी इस्तेमाल करना शुरू किया है। सरकारें और राजनीतिक दल खैरात का प्रयोग करने से बचें। यह तो स्वाभाविक है क्योंकि वे क्यों स्वीकार करेंगे कि वे अपने पापों का बोझ हल्का करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं या उसका वायदा करके चुनाव लड़ रहे हैं।

मीडिया अगर ज्यादा ईमानदार होता तो राजनेताओं और सरकारों की इच्छा की परवाह न करता। दक्षिण की राजनीति में, खासकर तमिलनाडु में फ्रीबीज का चलन काफी समय से था लेकिन देश के स्तर पर कोरोना के दौर में सरकार द्वारा 5 किलो मुफ्त राशन देने के फैसले के बाद इसका चलन अचानक बढ़ा है क्योंकि कोरोना के बाद हुए चुनाव में भाजपा को इस फैसले का लाभ मिलने का रुझान बहुत साफ दिखा। पर कोरोना के समय गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराना और साथ ही अनाज से भरे सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों को सड़ाने की जगह बांटने का विकल्प बहुत बढिया था और अगर बोनस में नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी तो उससे किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर लॉकडाऊन का फैसला गलत था और उससे खास तौर से प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट हुआ तो अनाज बांटने का सही फैसला करने का श्रेय भी देना चाहिए। लेकिन एक बार चुनावी लाभ देख लेने के बाद लगातार मुफ्त अनाज बांटने का फैसला निश्चित रूप से राजनीति का हिस्सा है और इसको अलग नजरिए से देखना चाहिए। यह अलग बात है कि उसके बाद से महिलाओं को, बेरोजगारों को, दलितों-आदिवासियों को, किसानों को (मुफ्त बिजली और कर्ज माफी समेत) बेहतर खरीद मूल्य देने, सालाना सहायता देने और कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना न जाने किस-किस तरह के लाभ देने की घोषणा करने की होड़ शुरू हो गई। और हालत यह हो गई कि कई जगहों से इन वायदों को पूरा करने लायक बजट न होने, योजनाओं के बीच में लटकने और शुरू भी न हो पाने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इनसे और कुछ हुआ या नहीं भाजपा और कांग्रेस को एक-दूसरे पर औकात से ज्यादा बड़े वायदे करने और वायादाखिलाफी करने का आरोप लगाने का अवसर मिल गया। वायदों की राजनीति एक है और वायदाखिलाफी की राजनीति दूसरी। लेकिन यह गंभीर मसला है और इसे सिर्फ राज्यों या केंद्र के बजट, घाटे, कर्ज जैसे राजकोषीय प्रबंधन वाली शब्दावली में उलझना गलत है।

खैरात (राजनेताओं के अपराधबोध और पाप का भागीदार बनकर उनको माफ कर देना अर्थात रेवड़ी पाकर वोट देना) का तत्व होने के बावजूद इनको खैरात या मुफ्त की रेवड़ी कहना गलत है और बड़े-बड़े वायदे करने वाले राजनेताओं को हल्का मान लेना गलत है। हमारे यहां यह सब वायदे और फैसले बड़ी पार्टियां, बड़े नेता और केंद्र तथा राज्य सरकारें कर रही हैं और इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो आज वायदे करे, कल वोट ले और परसों रफूचक्कर हो जाए। मोदी सरकार से जुड़े तमाम विवादों और वादाखिलाफी के बाद भी उसकी विश्वसनीयता इतनी है कि जब वे किसानों को साल में 6000 रुपए देने का वायदा करते हैं (और देते हैं) तो लोग उन पर भरोसा करते हैं और राहुल गांधी द्वारा 6000 रुपए प्रति माह देने के वायदे पर भरोसा नहीं करते। मोदी और राहुल का ग्राफ अगर ऊपर-नीचे होता है तो उसमें इन चुनावी वायदों और चालाकियों का भी हाथ है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन की बेहतर सफलता के पीछे उनके वायदों पर बढ़ता भरोसा रहा। मोदी के खिलाफ एंटी-इंकम्बैन्सी भी थी।

राहुल लाख झोंपडियों में जाएं, मोची का काम सीखें, रोड साइड सैलून में मालिश कराएं लेकिन उनकी पदयात्रा भी सैंकड़ों वातानुकूलित छावनियों और बसों-गाडियों वाली ही होती है। गरीब दलित/आदिवासी के घर पहुंचने पर उनके मन में भी अपराधबोध या अब तक की कांग्रेसी नीतियों की सीमाएं समझ आती होंगी। उनको मोदी जी की गलतियां दिखती हैं और मनमोहन सरकार की न दिखती हों, यह नहीं हो सकता।

और यह सोचने के बाद अगर हम फ्रीबीज पर विचार करेंगे तो यह खैरात, रेवड़ी और नेताओं/दलों का गैर-जवाबदेही वाला वायदा भर नहीं लगेगा। तब यह इन चीजों के हल्के प्रभाव भर का मामला दिखेगा। साफ लगेगा कि यह हमारी अब तक चली सरकारी नीतियों की विफलता का एक कोर्स करैक्शन है। यह सरकारों द्वारा अपनी नाकामी स्वीकारना है। अगर नई आर्थिक नीतियां हमारे योजनाबद्ध विकास के समाजवादी माडल या मिश्रित अर्थव्यवस्था की विफलता से पैदा हुई लगेंगी तो यह बदलाव डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर का लगेगा। सब कुछ गंवाकर अब उसे यही मिल रहा है तो आप उसे फ्रीबीज या रेवड़ी मत कहिए।

दोस्ती इतनी मजबूत हो कि लोग देखकर जलें: निमरत कौर

अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ कथित रिलेशन को लेकर कुछ लोग निमरत कौर को आलोचनाओं का शिकार बना रहे हैं और उन्हें ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरार का कारण मान रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। अफवाहें तब शुरू हुईं जब ऐसी खबरें आईं कि 2022 में फिल्म दसवीं की शूटिंग के दौरान अभिषेक और निमरत की दोस्ती गहरी हो गई थी। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर बातें होने लगीं। ऐश्वर्या के प्रशंसकों का मानना है कि अभिषेक की इस दोस्ती के कारण ऐश्वर्या के साथ उनके संबंधों में खटास आई है। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में टिप्पणियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसमें कुछ लोग निमरत पर अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, बच्चन परिवार के एक करीबी सूत्र ने इन अफवाहों को पूरी तरह से निराधार और शरारती बताया है। सूत्र का कहना है कि इस मामले में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक फिलहाल इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं और उन्हें किसी भी विवाद में पड़ने से बचने की सलाह दी गई है। इन अफवाहों के बीच, निमरत कौर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील साझा की। इस रील में वह एक ट्रेंडिंग डायलॉग पर लिप-सिंक करते हुए कह रही हैं कि दोस्ती इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लोग इसे देखकर जलें। इसके साथ उन्होंने लिखा, मेरी और केसी (करम चंद) की दोस्ती तो है ऐसीज अपने बीएफएफ को टैग करें!! इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इन अफवाहों को हल्के अंदाज में लिया और बताया कि वह अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीना पसंद करती हैं। निमरत ने कहा कि लोग हमेशा गपशप करेंगे, लेकिन इससे वह विचलित नहीं होतीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती हैं और इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देतीं। निमरत का कहना है कि वह अपने करियर और निजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने में विश्वास करती हैं, और ऐसी अफवाहें उनके लिए मायने नहीं रखतीं।बता दे कि बॉलीवुड अभिनेत्री निमरत कौर इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया में छाई हुई हैं। कुछ अफवाहें ऐसी चल रही हैं कि उनके और अभिनेता अभिषेक बच्चन के बीच कोई खास रिश्ता है, जो ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 ने कमाए 200 करोड़

हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 ने सिर्फ 10 दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। निर्देशक अनीस बज्मी और निर्माता भूषण कुमार की इस फिल्म ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया है। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, और त्रिप्ति डिमरी की स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म की सफलता में प्रमोशनल टूर ने बड़ी भूमिका निभाई है, जिसने दर्शकों के बीच उत्साह को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। प्रमोशन की शुरुआत जयपुर में एक भव्य ट्रेलर लॉन्च के साथ हुई, जिसके बाद टीम ने अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, नोएडा, इंदौर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में लाइव इवेंट्स किए। इन शहरों में दर्शकों ने फिल्म की टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और फैंस के बीच इसकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती गई। पुणे में कार्तिक आर्यन और माधुरी दीक्षित ने वड़ापाव जैसे लोकल स्नैक्स का आनंद लिया, वहीं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक कॉलेज इवेंट में कार्तिक और विद्या के साथ सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े। दुबई में एक भव्य इवेंट के दौरान, मिडिल ईस्ट से हजारों फैंस 'रूह बाबा' कार्तिक आर्यन से मिलने पहुंचे। इस इवेंट ने फिल्म की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता को साबित कर दिया। अब कार्तिक पटना में अपने फैंस से मिलने के साथ इस प्रमोशनल टूर का समापन करेंगे, जो हिंदी हार्टलैंड में अपनी पकड़ को मजबूत करेगा। कार्तिक आर्यन ने अपने इस सबसे बड़े प्रमोशनल कैंपेन में टीम के साथ कड़ी मेहनत की और हर इवेंट में दर्शकों से सीधा संवाद स्थापित किया। उनकी ऊर्जा और अपने फैंस के साथ जुड़ने की कोशिशों ने फिल्म को बड़े स्तर पर सफलता दिलाई।अब तक फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो इस फ्रैंचाइज़ी के लिए एक नया मील का पत्थर है। भूल भुलैया 3 ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

कैंसर को हराकर जीतने वाली मनीषा, आजकल है सिरदर्द से परेशान

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने लेटेस्ट पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि वह 'गंभीर सिरदर्द' से परेशान हैं। मनीषा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मंगलवार सुबह बिस्तर पर आराम करती हुई अपनी एक तस्वीर शेयर की। 'हीरामंडी- द डायमंड बाजार' अभिनेत्री ने बताया कि महीने में एक बार उन्हें 'गंभीर सिरदर्द' होता है और उन्हें नहीं पता कि इसका कारण क्या है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने इससे निपटने के तरीके भी बताए। मनीषा ने कैप्शन में लिखा फ्रसिरदर्द से जुड़ी परेशानियां...हेलो दोस्तों! मैं आज कुछ निजी बातें शेयर कर रही हूं और उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों को यह पसंद आएगी। मुझे महीने में एक बार गंभीर सिरदर्द होता है और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह पानी की कमी की वजह से है या नींद की कमी से, खराब भोजन या तनाव है? या यह सब कुछ है? इसके बाद अभिनेत्री ने सुझाव भी लिखे जो उनकी मदद करते हैं। मेरा समाधान? एक या दो दिन के लिए सब कुछ बंद कर देना, आरामदेह ऑडियोबुक या संगीत सुनना, हल्का खाना, खूब पानी पीना और दवाएं लेना शामिल है। क्या किसी और को भी ऐसा अनुभव हुआ है? आप इससे कैसे निपटते हैं? मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं! आपके सुझाव और तरकीबें शेयर करने से मुझे और दूसरों को भी राहत मिल सकती है। कैंसर से जंग लड़कर जीत हासिल करने वाली मनीषा ने चुनौतीपूर्ण यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उन्हें साल 2012 में ओवेरियन कैंसर का पता चला था। उन्होंने कहा मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल न केवल कैंसर रोगियों की मदद करने के लिए बल्कि स्वास्थ्य सेवा की जरुरत और ओवेरियन कैंसर के संकेतों और लक्षणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी करना चाहती हूं। मनीषा कोइराला ने आगे कहा कि खुद कैंसर का सामना करने के बाद मैं जानती हूं कि यह यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और मेरा मानना ??है कि यह जरुरी है कि हम सभी दूसरों के लिए आगे आएं और उनकी मदद करें। मनीषा ने कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क में करवाया और 2014 में वह ठीक हो गईं। वर्कफ्रंट की बात करें तो मनीषा कोइराला इस साल संजय लीला भंसाली के निर्देशन में तैयार सीरीज हीरामंडी- द डायमंड बाजार में मल्लिकाजान के रूप में नजर आईं। मनीषा इससे पहले संजय लीला भंसाली के साथ खामोशी- द म्यूजिकल में काम कर चुकी हैं। फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। रोमांटिक फिल्म में मनीषा के साथ सलमान खान, नाना पाटेकर समेत अन्य स्टार्स ने अहम रोल निभाया था।

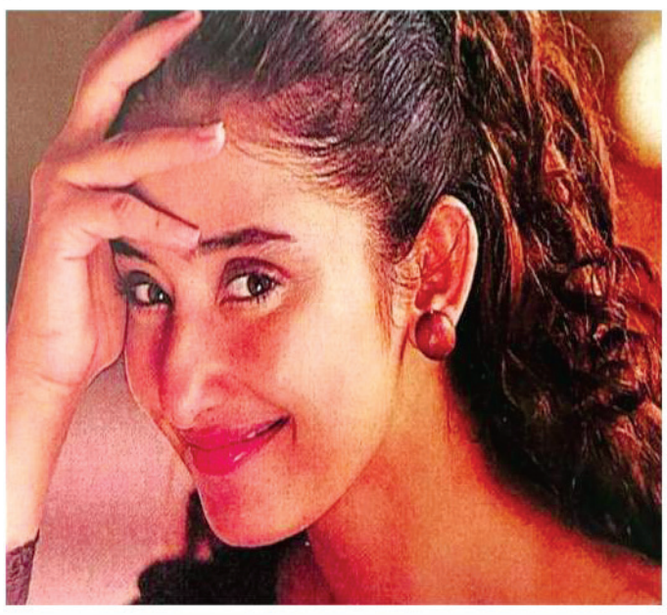

'कूल' रहने का अनोखा तरीका दिखाया सारा ने

हाल ही में अपने फैंस के साथ अभिनेत्री सारा अली खान ने एक मजेदार रील साझा की है। इस रील में उन्होंने फ्रकूलफ्र रहने का एक अनोखा तरीका दिखाया है। यह रील सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट की, जिसमें वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी टीम की एक सदस्य के साथ नजर आ रही हैं।
रील में सारा के हाथ में खीरा है, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए दिखाया। इसके साथ ही पास में बर्फ भी रखा हुआ है। सारा ने रील को कैप्शन देते हुए लिखा, 'खीरे की तरह ठंडे हो जाओ और बर्फ को आंख के नीचे लगाओ।' उनकी इस पोस्ट ने उनके फैंस को आकर्षित किया, और फैंस उनकी इस मजेदार सलाह का आनंद ले रहे हैं। सारा अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए हमेशा फैंस के साथ जुड़े रहने का प्रयास करती हैं। कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपने नाइट शूट के दौरान सेट से एक तस्वीर साझा की, जिसमें खूबसूरत अर्धचंद्र दिखाई दे रहा था। सारा ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'आज सेट पर नया मेहमान आया चंदू जी, बहुत समय बाद किस्मत ने कराया दीदार।'
इसके साथ ही उन्होंने पहले शूटिंग सेट से सूरज की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे खूबसूरत पलों को भी फैंस के साथ बांटना पसंद करती हैं। सारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल वह अमर कौशिक की अनटाइटल्ड जासूसी कॉमेडी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग मनाली, हिमाचल प्रदेश में चल रही है, और फैंस को इस नई जोड़ी का बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार है।

समंदर के किनारे ग्लेमरस अंदाज में नजर आई बिपाशा

हाल ही में अभिनेत्री बिपाशा बसु ने अपनी बेटी देवी और पति करण सिंह ग्रोवर के साथ बिताए प्यारे पलों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। पोस्ट में बिपाशा ने कैप्शन दिया, माई वाइब (मेरी विशिष्ट भावना)। एक्ट्रेस इन तस्वीरों में समंदर के किनारे धूप का चश्मा पहने और लेपर्ड प्रिंट वन पीस में नजर आ रही हैं, जो उनके ग्लैमरस अंदाज को बखूबी बयां कर रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी बिपाशा ने अपनी बेटी देवी और पति करण के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में करण, देवी को गोद में लिए हुए हैं, जबकि बिपाशा मुस्कुराते हुए साथ खड़ी हैं। अभिनेत्री ने रेत पर और पानी के किनारे चलते हुए वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जो फैंस को उनके जीवन की झलकियां दिखाते हैं। इससे पहले भी बिपाशा ने करण के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की थीं और उन्हें माइन (मेरा) कैप्शन दिया था। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर प्यारे कैप्शन के साथ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उन्होंने मां को मिलियन-वॉट की स्माइल वाली और किसी हीरे से ज्यादा चमकती कहा। बिपाशा की मां ने अपनी नातिन देवी के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते हुए एक प्यारे वीडियो में नाचते और हंसते हुए नजर आईं। बिपाशा बसु ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 2001 में फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। उनकी अगली फिल्म राज में उनके काम को काफी सराहा गया, और इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 2016 में उन्होंने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की और 2022 में उनकी बेटी देवी का जन्म हुआ। बिपाशा अपने फैंस को अपने जीवन के खूबसूरत पलों से जोड़े रखती हैं, और उनकी पोस्ट्स को फैंस का भरपूर प्यार मिलता है। बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री बिपाशा बसु अपने परिवार के साथ बिताए खास पलों को सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं।

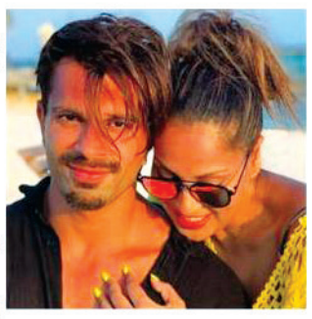

रवीना ने लिया बेसहारा जर्मन शेफर्ड को गोद

अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक बेसहारा जर्मन शेफर्ड को गोद लिया है। यह जानकारी रवीना टंडन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर दी। इस प्यारे वीडियो में रवीना अपने नए पालतू जानवर एल्सा का स्वागत करती नजर आ रही हैं, जिसे बारिश के दौरान हाईवे पर छोड़ दिया गया था। रवीना ने बताया कि पावडॉप्ट नामक संस्था की टीम ने एल्सा को बचाया और उसे नया जीवन दिया।रवीना ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के साथ एक भावुक संदेश भी साझा किया। उन्होंने लिखा, इस दीपावली हमारा दिल और बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे परिवार में एल्सा नाम की एक प्यारी जर्मन शेफर्ड जुड़ी है। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उनके अन्य पालतू जानवर, जिनमें अलास्का नामक हस्की भी शामिल है, सभी को उन्होंने गोद लिया है।रवीना ने अपने पोस्ट में लोगों से अपील करते हुए कहा, पालतू जानवरों को छोड़ना दिल तोड़ने वाला होता है। जो लोग पालतू जानवर अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे उन्हें पूरे दिल से अपनाएं। हर जानवर को एक प्यारभरा घर मिलना चाहिए, न कि अनिश्चित भविष्य। उन्होंने एल्सा के जीवन को सुरक्षित करने में मदद करने वाले सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि उनके घर में एल्सा को ढेर सारा प्यार और खुशी मिलेगी। इसके अलावा, रवीना की बेटी राशा थडानी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हैं। वह अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद से डेब्यू करेंगी, जिसमें अभिनेता अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

तलाक के बाद भी किरण से बेहतर पति बनने की टिप्स मांगता हूं: आमिर खान

सोलह साल साथ बिताने के बाद एक्टर आमिर खान और किरण राव अब अलग-अलग हो चुके हैं, इसके बावजूद उनके बीच बेहतर बांडिंग देखी जा सकती है। दोनों ने अब हाल ही में अपने सक्सेसफुल कोलैब्रेशन को लेकर बात की। इस बारे में आमिर ने कहा कि तलाक ने उनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खराब नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह तलाक के बाद भी किरण से बेहतर पति बनने की टिप्स मांगते हैं। वहीं कहते हैं कि अगर किरण मुझसे पूछें तो मैं उन्हें भी अच्छी पत्नी बनने की सलाह दे सकता हूं। दरअसल, एक ताजा इंटरव्यू में किरण ने कहा कि आमिर के साथ काम करके मजा आता है। वह पावरहाउस हैं। वहीं आमिर ने कहा कि तलाक एक अलग टॉपिक है लेकिन क्रिएटिव इंसान की तरह हम साथ में काफी अच्छा करते हैं। हमें एक-दूसरे के आइडिया पसंद आते हैं। किरण आगे कहती हैं कि कई चीजें हैं जो हमें पसंद हैं। लेकिन जब कोई चीज पसंद नहीं होती तो मैं उनके पास जाती हूं और वह अच्छे से समझाते हैं। हम एक-दूसरे के ओपीनियन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। यही वजह है कि हमारी पार्टनरशिप इतनी लंबी चली। आमिर फिर मस्ती करते हुए कहते हैं कि वह कई बार किरण से अच्छे पति होने की सलाह मांगते हैं। इस पर किरण कई पॉइंट्स बता देती हैं। वह कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या मेहमान हमारे घर आते हैं तो मैं बहुत बातों में लग जाता हूं और कई स्टोरी सुनाता हूं। किरण फिर पूछती हैं कि अब आप पब्लिकली सब बताओगे तो आमिर बोलते हैं तू चुप रह। आमिर आगे बोलते हैं कि किरण, लेकिन मुझसे नहीं पूछती कि मैं कैसे अच्छी पत्नी बनूं? आप मुझसे पूछो मैं आपको लिस्ट बताता हूं। किरण फिर बोलती हैं कि अच्छी बात यह है कि मैं एक्स वाइफ हूं, इसलिए मुझे नहीं जानना है।
बता दें कि आमिर और किरण ने 4 साल की डेटिंग के बाद साल 2005 में शादी की थी। दोनों का बेटा भी है आजाद। साल 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने की घोषणा की थी। बता दें कि आमिर खान और किरण राव का तलाक हो गया है। दोनों ने 16 साल की शादी को साल 2021 में तोड़ दिया था। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड है और हमेशा एक-दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली सपोर्ट करते हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जैसे दंगल, धोबी घाट, पीपली लाइव और लापता लेडीज।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर रवाना हुए मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को

नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने प्रस्थान वक्तव्य में, प्रधान मंत्री ने कहा कि यह नाइजीरिया की उनकी पहली यात्रा होगी, जो पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में भारत का करीबी भागीदार है। मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर होगी, जो लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित है। उन्होंने नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के साथ-साथ उन नाइजीरियाई लोगों से भी मिलने की उत्सुकता व्यक्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदी में स्वागत संदेश भेजे हैं। मोदी ट्रोइका सदस्य के रूप में 19वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने जी-20 को लोगों के जी-20 में बदल दिया था और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को एजेंडे में शामिल किया था।

महायुति की हैट्रिक जीत पर एकनाथ शिंदे की नजर

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने

कहा कि महायुति सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में हैट्रिक जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है और तीसरे दौर के चुनाव में निर्णायक बहुमत हासिल करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में हैट्रिक जीत हासिल करने के लिए तैयार है, उन्होंने इसकी तुलना क्रिकेट मैच से की जहां लक्ष्य साफ, शक्तिशाली जीत की ओर होता है। मुंबई के दहिसर में एक जनता को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम दो बार चुने गए हैं और अब हैट्रिक की बारी है। हमें प्रतिद्वंद्वी का विकेट लेना है और इसे अच्छे बहुमत से लेना है। शिंदे ने कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है, हमें तीसरी बार हैट्रिक करनी है और सीधा सिक्सर लगाना है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रभावी शासन के लिए जनता के साथ सीधे संवाद की आवश्यकता होती है।

दिग्विजय ने महायुति को बताया चोरी की सरकार

नईदिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने

का भरोसा जताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महायुति को चोरी की सरकार बताया। उन्होंने बताया कि जनता ने पहले कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा गठबंधन को चुना था। उन्होंने महायुति पर झारखंड सरकार को भी गिराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि महायुति बिना किसी वजह के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह चोरी की सरकार है। यह सार्वजनिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा गठबंधन को चुना था। वे झारखंड में भी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वे मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज रहे हैं। अदालत भी उनसे सवाल करती है कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया। मुझे यकीन है कि झारखंड और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में 288 संसदीय सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है।

मतों के धर्म-युद्ध से करना होगा वोट-जिहाद का मुकाबला : देवेंद्र

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र

फडणवीस ने वोट जिहाद करने और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा इस वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एमवीए ने लोकसभा में वोट जिहाद का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि 12 सीटों पर, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वोट जिहाद के नारे लगाए गए और कहा कि भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए धार्मिक स्थानों और नेताओं को अल्लाह के नाम पर शपथ दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर एमवीए इस तरह वोट जिहाद करेगा, तो धर्म युद्ध की अपरिहार्य आवश्यकता होगी। फडणवीस ने आरोप लगाया कि मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।

फडणवीस के धर्मयुद्ध वाले बयान पर राउत का पलटवार

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस लगातार धर्मयुद्ध वाला बयान दे रहे है। ऐसे में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से पलटवार किया जा रहा है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने फडणवीस को धर्मद्रोही बताया और उन पर राज्य की एकता की विरासत को धोखा देने का आरोप लगाया। राउत की टिप्पणी फडणवीस के इस दावे के जवाब में आई है कि विपक्ष वोट जिहाद में संलग्न है, और मतदाताओं से मतपत्रों के धर्मयुद्ध के साथ इसका प्रतिकार करने का आग्रह किया है। राउत ने विधान सभा चुनाव की स्थानीय प्रकृति पर जोर देते हुए पाकिस्तान में भारतीय ध्वज की मेजबानी के बारे में फडणवीस के बयान की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव में, वे झारखंड जाते हैं और 'धर्मयुद्ध' की बात करते हैं। महाराष्ट्र में, केवल एक ही धर्म है, और वह छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है, जो इसकी रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट करती है।

वोटबैंक पॉलिटिक्स नहीं लोगों के विकास पर हमारा ध्यान: मोदी

नईदिल्ली। एचटी लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि कैसे उनका प्रशासन वोट बैंक की राजनीति से बचकर और लोगों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करके पिछली सरकारों से अलग है। उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में विस्तार से बताया, जो भारतीय जनता द्वारा उस पर दिए गए विश्वास पर आधारित है। मोदी के संबोधन ने सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के खिलाफ सरकार के लचीलेपन के युग को रेखांकित किया, चुनौतियों के बीच राष्ट्र की प्रगति के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है कि नीतियां भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हों, जो पिछले प्रशासनों की चुनावी और वोट-बैंक से प्रेरित रणनीतियों से अलग हटकर हैं। इस दृष्टिकोण ने न केवल सरकार में लोगों के विश्वास को बहाल किया है, बल्कि भारत को अभूतपूर्व महत्वाकांक्षाओं से भरे रास्ते पर भी स्थापित किया है जो नीति-निर्माण को आकार देते हैं। जैसा कि मोदी ने बताया, सरकार का ध्यान पूरी तरह से इन आकांक्षाओं को पूरा करने पर है, जो देश में शासन को कैसे माना जाता है और कैसे लागू किया जाता है, इस प्रतिमान बदलाव का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में हुए आर्थिक बदलावों पर गर्व से बात की, जिसने भारतीयों में जोखिम उठाने की संस्कृति को फिर से जगा दिया है। 2014 में 16 लाख करोड़ से बढ़कर आज 48 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचे केंद्रीय बजट का बढ़ना देश के आर्थिक विस्तार का उदाहरण है।

पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ, शिक्षा, अनुसंधान और बुनियादी ढाँचे में निवेश में वृद्धि हुई है, जो सार्वजनिक लाभ के लिए पर्याप्त खर्च करने की सरकार की प्राथमिकता

को दर्शाता है। यह राजकोषीय रणनीति पिछले अभ्यासों से अलग है, जिसका उद्देश्य देश के विकास पथ को बढ़ाना है।

सरकार की नीतियों के ठोस परिणामों में से एक भारतीय घरों में एलपीजी गैस कनेक्शनों में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो लंबे समय से चली आ रही पहुंच की समस्या का समाधान है। मोदी ने कहा कि 2014 में 14 करोड़ कनेक्शनों से यह संख्या बढ़कर 30 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे गैस की कमी की समस्या प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। यह उपलब्धि न केवल जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीतियों के व्यावहारिक प्रभाव को भी दर्शाती है।

26/11 के मुंबई आतंकी हमलों पर विचार करते हुए, मोदी ने बदले हुए सुरक्षा परिदृश्य पर टिप्पणी की, जहाँ आतंकवादी अब असुरक्षित महसूस करते हैं। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के मजबूत रुख को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरों से निर्णायक रूप से निपटा जाए। इस परिवर्तन का उल्लेख बाहरी खतरों के खिलाफ देश की सुरक्षा में की गई प्रगति की याद दिलाता है, भारत की संप्रभुता और उसके लोगों की सुरक्षा की रक्षा करने में सरकार के संकल्प को मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य भाषण ने एक ऐसी सरकार पर प्रकाश डाला जो राजनीतिक स्वार्थ से ज़्यादा लोगों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देती है। महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों, बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों को ठोस लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित करके, मोदी के प्रशासन ने एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की यात्रा शुरू की है। जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है, सरकार का शासन के प्रति दृढ़ दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि नीति-निर्माण में नागरिकों की आकांक्षाएँ सबसे आगे रहें।

महाराष्ट्र के लोग महायुति से खुश

20 नवंबर को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के हिस्से के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में, मोदी ने चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति (महागठबंधन) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बूथ-स्तरीय प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने पिछले कई महीनों में भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों को स्वीकार करते हुए उनके समर्पण को लोकतंत्र के लिए महान तपस्या बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है और आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय भी नजदीक है। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे।

मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल से बहुत प्रभावित हैं। मैं जहां-जहां गया हूं, मैंने ये प्यार देखा है। वो भी चाहते ?हैं? कि अगले पांच साल यही सरकार रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में गूंज रहा है- भाजप-महायुती आहे, तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार, समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। यही फर्क है, हमारी और अघाड़ी वालों की सरकार में और इस फर्क को लोग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारी सरकार का विजन है कि हम मिलकर इतना विकास करें कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास पता है, जब तक देश में एससी-एसटी-ओबीसी समाज जागरूक नहीं हुआ था, तब तक केंद्र में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। लेकिन जब से एससी-एसटी-ओबीसी समाज एकजुट हुआ है, तब से कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती चली गई। इसलिए कांग्रेस अब एससी-एसटी-ओबीसी समाज को इतना तोड़ देना चाहती है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई ताकत ही न बचे। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के मजबूत सिपाही हैं, आप लोग मोदी के सीधे प्रतिनिधि हैं। लोग आपसे अपनी आशाएं, आकांक्षाएं बता कर आश्वस्त होते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बता दिया तो मोदी को बता दिया। मेरा भी प्रयास रहता है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी हकीकत मुझ तक पहुंचती रहे।

समय बदल गया है, अब आतंकी अपने घरों में भी डरते हैं: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति की, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारें लोगों में उस उत्साह का संचार नहीं कर पाईं, जो जोखिम लेने के लिए जरूरी था। बीते 10 वर्षों में हमने देश के युवाओं में जोखिम लेने की क्षमता विकसित की है। इसी का नतीजा है कि देश में अब 1.25 लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं और अब युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए ललायित है।

अंतिम चरण के प्रचार में सपा-भाजपा के बीच शह-मात का खेल जारी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी जिस करहल विधानसभा क्षेत्र को मुलायम सिंह यादव के समय से अपने दबदबे वाली सीट मानता था, उस सीट पर होने वाले उप चुनाव में अब मुलायम कुनबे के ही दो सदस्यों के आमने-सामने आने से एक तरफ सपा प्रमुख को यादव वोट बैंक में बिखराव होते नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ इस चुनावी रण ने एक भाई-बहन के रिश्तों में दरार भी डाल दी है। इतना ही नहीं मुलायम परिवार में पड़ी दरार को लेकर यहां की जनता का यह भी कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह की तरह उनके बेटे अखिलेश कुनबे को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। इस अंतर्द्वंद के बीच अखिलेश के माथे पर इस बात की भी शिकन नजर आ रही हैं कि कहीं वह यहां से जीती हुई बाजी हार नहीं जायें। भाजपा ने यहां से मुलायम परिवार के अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाकर यादव वोट बैंक में सेंधमारी का दांव चला है। बता दें बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश की पत्नी संध्या यादव और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बहन-भाई हैं। संध्या अपने पति के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। उनके साथ संध्या की सास पूर्व विधायक उर्मिला यादव भी गांव-गांव वोटों के लिए पसीना बहा रही हैं। सास-बहू की जोड़ी ने यादव मतदाताओं के समीकरणों में हलचल मचा दी है।

खैर, करहल विधान सीट पर भाजपा का सबसे ज्यादा जोर घिरोर और बरनाहल क्षेत्र में दिख रहा है। ऐसे में सपा ने भी अपनी ताकत इन्हीं क्षेत्रों में झोंक रखी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बार-बार घिरोर क्षेत्र में ही जनसभा करने आ रहे हैं। सपा का गढ़ कही जाने वाली करहल विधानसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यहां सवा लाख के करीब यादव मतदाता हैं। इस सीट पर 1985 के बाद से लगातार यादव चेहरों को ही जीत मिलती रही है। 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से प्रत्याशी

बने थे। अब उपचुनाव के लिए सपा ने अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद एवं पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस बार रणनीति बदलते हुए अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। यादव चेहरा होने के साथ वह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई भी हैं। उनकी मां उर्मिला यादव दो बार घिरोर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। यह सीट 2007 के बाद परिसीमन में समाप्त हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा वर्तमान में करहल विधानसभा क्षेत्र में शामिल है।

भाजपा यहां यादव मतों में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव और भाजपा नेता तो यादव वोटरों से वोट मांग ही रहे हैं, मुलायम परिवार की बेटी संध्या यादव और समधन उर्मिला यादव भी प्रचार में लगी हुई हैं। सास-बहू के ज्यादातर कार्यक्रम घिरोर और बरनाहल क्षेत्र के यादव बहुल गांवों में लगाए जा रहे हैं। भाजपा इस बार सपा के गढ़ को ढहाने के दावों में जुटी हैं। भाजपा की इस रणनीति की काट के लिए सपा ने भी ताकत लगा दी है। इसी वजह से दीवाली के बाद से सपा सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव यहां पांच दिन लगातार नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। शिवपाल यादव भी तीन सभाएं कर चुके हैं। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिये यहां 18 नवंबर की शाम से प्रचार बंद हो जायेगा। प्रचार के अंतिम चरण में सैफई परिवार करहल में पूरी ताकत झोंके हुए है। यहां गत दिवस शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा हुई थी।

खेल
प्रमुख समाचार

बीसीसीआई के सामने पीसीबी फिर पस्त

कराची। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

(बीसीसीआई) ने पाकिस्तान के दौरे के कार्यक्रम में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को शामिल करने के पीसीबी के कदम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के साथ आपत्ति दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे को तीन मेजबान शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक सीमित करने पर सहमत हो गया है। पीसीबी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, तैयार हो जाओ पाकिस्तान! आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रॉफी टूर 16 नवंबर को इस्लामाबाद में शुरू होगा और ट्रॉफी स्कार्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद का भी दौरा करेगी। इसके बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईसीसी के समक्ष विरोध दर्ज कराया था।

पीसीबी के एक सूत्र ने बताया, पीसीबी पहले से ही आईसीसी के साथ चर्चा कर रहा है कि ट्रॉफी यात्रा को कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में बढ़ावा मिलता रहे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी यात्रा की योजना सलाह मशविरे और आईसीसी की मंजूरी के बाद बनाई गई थी।

पीसीबी ने ट्रॉफी दौरे का कार्यक्रम एकतरफा तय नहीं किया था। बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जय शाह, जो एक दिसंबर को आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आईसीसी से कहा कि यह अस्वीकार्य है कि पीसीबी पीओके में ट्रॉफी दौरे की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई सचिव शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चैंपियंस ट्रॉफी यात्रा के आयोजन के पीसीबी के विचार पर आपत्ति जताई थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत की इक्विटी बाजार ने चीन से भी बेहतर रिटर्न्स दिए

मुंबई। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2000 से अब तक भारत के इक्विटी बाजार ने चीन के इक्विटी बाजार से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। यह रिपोर्ट ड्यूश बैंक ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने शानदार आर्थिक प्रगति की है और इसके इक्विटी बाजार का प्रदर्शन भी ठीक-ठाक रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में भारत के इक्विटी बाजार ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2000 से अब तक चीन के इक्विटी बाजार ने जहां सालाना औसतन 4.0 प्रतिशत के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं भारत के इक्विटी बाजार ने इस अवधि के दौरान 6.9 प्रतिशत की सालाना दर से शानदार रिटर्न्स दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का इक्विटी बाजार सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला बाजार रहा फिर चाहे वो उभरते हुए बाजार हों या फिर विकसित बाजार।

आईएमएफ के लिए चिंता का सबब बना कंगाल पाकिस्तान

नईदिल्ली। आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने पाकिस्तान को दिए गए 7 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज की शर्तों को लागू करने में कुछ बड़ी चिंताओं को जाहिर किया है। इनमें प्रमुख रूप से टैक्स संग्रह में कमी और विदेशी कर्ज हासिल करने में देरी शामिल हैं। पांच दिनों तक चली गहन बैठकों के बाद, आईएमएफ ने पंजाब के नए कृषि आयकर कानून पर भी चिंता जताई, जो अभी तक संघीय कानूनों के अनुरूप नहीं है और राष्ट्रीय वित्तीय समझौते (नेशनल फिस्कल पैक्ट) से अलग है। आईएमएफ की मुख्य चिंताओं में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) का खराब प्रदर्शन: यह टैक्स संग्रह के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। विदेशी कर्ज में देरी: पाकिस्तान अभी भी 2.5 अरब के वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज का इंतजार कर रहा है।

गिरने लगे प्याज के दाम जल्द और राहत की उम्मीद

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। इस सप्ताह प्याज की औसत खुदरा कीमत 67 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 63 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सरकार को उम्मीद है कि अगले 1-2 सप्ताह में कीमतों में और कमी आएगी। राजस्थान के अलवर में प्याज की फसल लगभग तैयार हो गई है। हालांकि, दिवाली और छठ पर्व के दौरान खेतों में मजदूरों की कमी के कारण फसल की कटाई और ढुलाई में देरी हुई है। सरकारी सहकारी समितियां नैफेड और एनसीसीएफ ने प्याज की सप्लाई बढ़ा दी है। सरकार ने इस साल 4.75 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया है। पहले दिल्ली में प्याज की सप्लाई ट्रकों के जरिए होती थी लेकिन अब इसे मालगाड़ियों के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे एक बार में लगभग 1400 टन प्याज दिल्ली पहुंच रही है। पिछले सप्ताह दो मालगाड़ियां प्याज लेकर दिल्ली पहुंची थीं और एक और मालगाड़ी नासिक से रवाना हो रही है।

ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड से जमकर हुआ पेमेंट

नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी में यह इस्तेमाल कुछ ज्यादा है। खासतौर से ई-कॉमर्स कंपनियों से। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में 1,76,201 करोड़ रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च हुए। इनमें से सबसे ज्यादा रकम ऑनलाइन खरीदारी में खर्च हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने ऑनलाइन खरीदी में 1,15,168 करोड़ रुपये ऑनलाइन खर्च किए। यह सितंबर में कुल खर्च का करीब 65त्न है। जानकारों के मुताबिक ई-कॉमर्स छूट के कारण क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन खर्च में तेजी जारी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मूल्य कुछ समय के लिए इन-स्टोर पेमेंट से आगे निकल गया है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मात्रा अभी भी फिजिकल ट्रांजेक्शन से पीछे है।

देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कृषि की घटती हिस्सेदारी

रमेश चंद

विकास में कृषि की भूमिका संबंधी तमाम दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कृषि की घटती हिस्सेदारी को दर्शाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के निम्न आय से मध्य एवं उच्च आय की ओर रुख करने के साथ ही इसकी रोजगार में हिस्सेदारी में गिरावट का भी पता चलता है। इसी आधार पर वृद्धि एवं विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों में भी अब गैर कृषि क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है।

इस विचार की जड़ ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर लुईस (1954) के काम में दिखती है। उन्होंने आर्थिक विकास का वर्णन वृद्धि की उस प्रक्रिया के तौर पर किया है जिसके तहत संसाधन कम उत्पादकता एवं पारंपरिक तकनीक वाले कृषि क्षेत्र से अधिक उत्पादकता वाले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं। यह सिद्धांत आर्थिक विकास में कृषि की काफी निष्क्रिय भूमिका बताता है, लेकिन औद्योगीकरण का समर्थन करने वाले कई विकासशील देश बड़े पैमाने पर अपने उद्योगों को सहारा देने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं।

हरित क्रांति के बाद विकास के लुईस मॉडल की कुछ धारणाओं का खंडन किया गया। पहले, हरित क्रांति से पता चला कि प्रौद्योगिकी कृषि को आधुनिक बनाने और उद्योग की कल्पना के अनुसार अधिशेष पैदा करने में महती भूमिका निभा सकती है। दूसरा, खेती में श्रम की असीमित आपूर्ति की धारणा भी अब मान्य नहीं रही है। इन बदलावों का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक बदलाव के मॉडल पर असर पड़ता है।

विकासशील और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के मामले में बीते तीन से चार दशकों का अनुभव दर्शाता है कि कार्यबल को कृषि से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया काफी धीमी है और ये सुचारु भी नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी कृषि की हिस्सेदारी में काफी तेजी से गिरावट देखी जा रही है जबकि रोजगार हिस्सेदारी में काफी कम गिरावट आई है।

यह आर्थिक बदलाव एवं विकास के विभिन्न चरणों में बड़ी संख्या में देशों के अनुभव से देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सन् 1991 से 2021 के बीच तीन दशकों के दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी (साल 2015 में डॉलर में मापा गया) चीन में 10 गुना से ज्यादा, वियतनाम में 4.8 गुना, भारत में 3.4 गुना और इंडोनेशिया में 2.4 गुना बढ़ गया। मगर इससे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता (प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित) पर असर नहीं पड़ा।

इन चार उभरते देशों में कृषि एवं गैर गैर कृषि के बीच प्रति कर्मचारी उत्पादकता अथवा आय में सबसे ज्यादा असमानता चीन में देखने को मिली, जहां बीते तीन दशकों में प्रति व्यक्ति आय और विनिर्माण उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज किया गया है। चीन में खेती करने वाला श्रमिक गैर कृषि श्रमिक की आय का सिर्फ एक चौथाई ही कमा पाता है। भारत और वियतनाम में भी चीन जैसी ही स्थिति है, लेकिन इंडोनेशिया में कम असमानता है।

इन अनुभवों से पता चलता है कि गैर कृषि अथवा तथाकथित आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में तेज वृद्धि से कृषि कार्यबल में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। नतीजतन, रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के उत्पादन अथवा आय में इसकी हिस्सेदारी से बहुत ज्यादा रही। ये चीन में तीन गुना, भारत और वियतनाम में ढाई गुना तथा इंडोनेशिया में दोगुना से अधिक रही।

ढांचागत बदलाव के पारंपरिक मॉडल के कुछ अन्य विरोधाभास भी हैं। जैसे- पहला, दक्षिण अफ्रीका में प्रति व्यक्ति आय और विकास के काफी उच्च स्तर पर प्रति कामगार आय में सर्वाधिक असमानता भी दर्शाता है। वहां का एक कृषि श्रमिक गैर कृषि श्रमिक की आय के दसवें हिस्से से भी कम कमाता है। दूसरा, कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ देशों में और पूरे विश्व में हाल के समय में बढ़ी है।

विश्व पर्यटन मानचित्र में बस्तर के धुड़मारास गांव ने बनाई अपनी जगह

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धुड़मारास की सफलता का मुख्य श्रेय यहां के स्थानीय निवासियों को जाता है, जिन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों को संरक्षित रखते हुए इसे आकर्षक पर्यटक स्थल में बदल दिया है। धुड़मारास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के अदभुत आदिवासी जीवनशैली, पारम्परिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक

स्थल है।

धुड़मारास गांव दुनियाभर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। विश्व स्तर पर पर्यटन गांव के रूप में इस गांव की पहचान स्थापित होने का तात्पर्य यह भी है कि लंबे समय के बाद बस्तर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि धुड़मारास तथा बस्तर के ही चित्रकोट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था।

प्रकृति की गोद में बसा है धुड़मारासा गांव-प्रकृति की गोद में बसा धुड़मारास गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के बीच से बहती कांगेर नदी इसे मनमोहक बना देती है। बस्तर के लोग मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने से उन्हें रोजगार मिल रहा है। गांव के युवा पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों की सैर कराते हैं। स्थानीय खानपान के अंतर्गत पर्यटकों को बस्तर के पारम्परिक व्यंजन परोसे जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग ट्रेल और कैंपिंग साइट विकसित करने सहित होम-स्टे की सुलभता हेतु पहल कर रही है। साथ ही स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है, जिससे ईलाके के रहवासी ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता होने के साथ आय संवृद्धि हो सके।

राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण 4 दिसंबर को

स्कूलों की दक्षता बढ़ाना सुनिश्चित करें : परदेशी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण के मद्देजर स्कूलों की दक्षता बढ़ाने के लिए गंभीरता के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि आगामी माह के 4 दिसम्बर को कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों की दक्षता को राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है। इसके तहत केन्द्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा।

शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय व अकादमिक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण-2024 के आकलन कार्य के सभी जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं 146 विकासखंडों में बीईओ, बीआरसीसी तथा संकुल प्राचार्य को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शिक्षा सचिव श्री परदेशी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देश भर में एक साथ होने जा रहे इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ में भी

लागू किया जा चुका है। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में नवीन शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप कक्षा 3री, 6वीं और 9वीं में आधार भूत प्रारंभिक एवं मध्य चरणों के अंत में छात्रों की दक्षता का आकलन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ के मात्र छात्र-छात्रों का नहीं बल्कि, शिक्षक, स्कूल तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मूल्याँकन सिद्ध होगा, जिसके आधार पर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता का श्रेणी निर्धारण भी होगा ।

उन्होंने बताया कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कक्षा 3री के लिए भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया से 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएँगे। कक्षा 6वीं के लिए उक्त विषयों से संबंधित 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएँगे। कक्षा 9वीं में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट पर हल करने होंगे। परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र दिया जायेगा। परख मूल्याँकन माइनस मार्किंग नहीं होगी। केंद्र सरकार के नियमानुसार जिस माध्यम की शाला चयनित की गई, उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे अर्थात् प्रश्नपत्र होगा । यदि अंग्रेजी माध्यम की कई शाला सेम्पल शाला के रूप में चयनित की जाती हैं, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा में आकलन परीक्षा निर्धारित होगी। राज्य में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए सेंपल शालाओं के रूप में जिले की शासकीय सहित राज्य शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, केंद्रीय, नवोदय विद्यालयों को सीधे भारत शासन, स्कूल शिक्षा वि नई दिल्ली द्वारा चयनित व निर्धारण किया गया है।

बारनवापारा बना प्रवासी बाघ का स्थायी ठिकाना

रायपुर। महासमुंद के रास्ते बारनवापारा पहुंचे प्रवासी बाघ ने अभयारण्य के जंगलों को अपनी स्थायी टेरिटरी बना लिया है। 300 किलोमीटर के क्षेत्र में बाघ का नियमित विचरण हो रहा है। बाघ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महासमुंद और बलौदाबाजार वनमंडल के अधिकारी, कर्मचारी और एनजीओ की टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसके तहत एंटी स्नेयर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कोरिया जिले में जहर देकर एक बाघ को मारने की घटना के बाद अधिकारी किसी भी खतरे को टालने के लिए सतर्क हैं। महासमुंद के रास्ते सात मार्च को यह बाघ बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा। वन विभाग की योजना है कि बाघ की स्थायी टेरिटरी बन जाने के बाद इस क्षेत्र में एक मादा बाघ (टाइग्रेस) को लाया जाए ताकि बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके। एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी) के साथ हुई चर्चा के बाद अधिकारी मादा बाघ की तलाश में महाराष्ट्र भी गए थे, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बाघ की सुरक्षा के लिए दिन-रात मॉनिटरिंग- बारनवापारा में बाघ पूरी तरह

सुरक्षित है, क्योंकि यहां कोई दूसरा बाघ मौजूद नहीं है। इंसानों से संभावित खतरे के मद्देनजर महासमुंद डीएफओ पंकज राजपूत, एसडीओ मोहम्मद वाहिद खान और बलौदाबाजार डीएफओ मयंक अग्रवाल की निगरानी में टीम लगातार बाघ की स्थिति पर नजर रख रही है। एनजीओ की एंटी स्नेयर टीम दिन और रात में गश्त कर रही है।

चीतल और जंगली सुअर बने भोजन का मुख्य स्त्रोत- बारनवापारा अभयारण्य में चीतल और जंगली सुअरों की प्रचुरता है, जो बाघ के लिए भोजन का मुख्य स्त्रोत बने हुए हैं। शिकार के अवशेष जंगल में पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाघ ने इन्हीं जानवरों का शिकार किया है। जानकारों का मानना है कि बारनवापारा का माहौल बाघों के लिए अनुकूल है। मादा बाघ को यहां लाने से न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्र बाघ संरक्षण के लिए आदर्श बन सकता है। बाघों की संख्या बढ़ने से महासमुंद, सारंगढ़-बिलाईगढ़, और गोमर्डा वनमंडल को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नए बाघ टेरिटरी की तलाश में इन क्षेत्रों तक जा सकते हैं। वन विभाग जल्द से जल्द टाइग्रेस लाने के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके और जैव विविधता को समृद्ध किया जा सके।

गिद्ध संरक्षण पर कार्यशाला:बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड काउंट इंडिया के विशेषज्ञों ने दिए सुझाव

रायपुर। गिद्ध संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में शोधकर्ता, छात्र, और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए, जहां गिद्ध संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड काउंट इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के विशेषज्ञों ने गिद्धों की वर्तमान स्थिति, उनकी संख्या में गिरावट के कारण और उनके लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के उपायों पर चर्चा की। शोधकर्ताओं और छात्रों ने गिद्ध संरक्षण के महत्व और उससे संबंधित चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में न केवल गिद्ध संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया, बल्कि सभी प्रतिभागियों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी किया। शोधकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में गिद्धों की गणना से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व के प्रयासों को विशेष रूप से सराहा गया, जहां गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट और वल्चर सेफ जोन जैसी पहल की जा रही हैं। वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री प्रेम कुमार ने कहा कि गिद्ध संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग नागरिकों की भावनाओं को गिद्धों से जोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे वे इनके संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनें।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राजधानी में 62 लाख 71 हजार रुपये की चोरी

रायपुर। शहर के मुजगहन थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक़ यहां एक मकान से रहस्यमयी तरीके से 62 लाख 71 हजार रुपये पार कर लिए दिए है। यह रकम पीड़ित सोनकर परिवार ने अपने कमरे के दीवान में रखी हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया है कि यह रकम उन्हें जमीन की बिक्री से प्राप्त हुए थे। कुल रकम 2 करोड़ 41 लाख रुपए थी जबकि इसी रकम में से 62 लाख 71 हजार रुपये पार होने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित सोनकर परिवार ने यह भी दावा किया हैं कि पुलिस इस मामले में पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। वह पिछले महीने के 24 अक्टूबर से इस मामले की शिकायत करने पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी लेकिन उनकी शिकायत अबतक दर्ज नहीं की गई थी। बताया कि पुलिस की तरफ से त्यौहार होने की बात कहकर शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थे। हालाँकि अब बीस दिनों बाद मामले को संज्ञान में लते हुए शिकायत ले ली गई है। सूत्रों की मानें तो चोरी की इस वारदात को किसी करीबी द्वारा ही अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। चोरी की वारदात वाला घर एक संयुक्त परिवार है जहां अन्य सदस्य भी निवासरत है।

पशु आहार गोदाम में लगी भीषण आग

रायपुर। भनपुरी इलाके में स्थित महालक्ष्मी मोल्ड्स प्रा. लि. के पशु आहार गोदाम में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। इस आगजनी से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग और टीम पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फ्लिहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। पूरी घटना खमतराई थाना क्षेत्र का है। वहीं गोदाम में मौजूद सामान के जलने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फ्लिहाल दमकल कर्मियों द्वारा आग को बुझाने का काम जारी है, और पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

फार्म हाउस में हुक्का पीते 7 गिरफ्तार

रायपुर। ग्राम पिरदा स्थित सतपाल फार्म हाउस में हुक्का पीते 7 आरोपियों को विधानसभा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने 8 हुक्का पॉट के साथ दस हजार रुपए कीमत का 200 ग्राम फ्लेवर भी जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों में शेख सागर पिता शेख नवाबुद्दीन (29 वर्ष), शोएब आलम पिता अली हैदर (29 वर्ष), मनु शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा (24 वर्ष), श्रेष्ठ शर्मा पिता स्व. अजय शर्मा (24 वर्ष), अनमोल जदवानी पिता स्व. दिलीप जदवानी (24 वर्ष), विनेश लालवानी पिता देवपाल लालवानी (29 वर्ष) और संजय महानंद पिता अनुजा महानंद (39 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 698/2024 धारा 4 ए, 4बी, 21(1) कोटपा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

रामविचार ने मोदी को आदिवासियों का भगवान का अपमान किया

रायपुर। मंत्री राम विचार नेताम के मोदी को आदिवासीयो का भगवान वाले बयान की कड़ी निंदा करते हुए आदिवासी समाज से माफी की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्री राम विचार नेताम मोदी की चाटुकारिता में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें ईश्वर और इंसान में फर्क समझ नहीं आ रहा है। आदिवासी समाज के भगवान बुढादेव है और राम विचार नेताम बुढादेव के बजाये मोदी को भगवान बताकर समस्त आदिवासी समाज की आस्था पर चोट किया है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा लगातार आदिवासियों के संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ कर रही है। राम विचार नेताम के अपमान जनक बयान के लिए भाजपा को पूरे देश के आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिये। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से पूछा क्या मोदी मर्यादा श्री राम जी, भगवान शंकर जी और हमारे देवी देवताओं से बड़े हैं। क्या मोदी भगवान बिरसा मुंडा से ऊपर हो गए हैं जो उन्हें भाजपा नेता भगवान घोषित कर रहे हैं। क्या भाजपा मोदी को भगवान मानती है। भाजपा के लिए मोदी भगवान हो सकते हैं लेकिन समस्त जनता के लिए भगवान हमारे देवी देवता ही हैं।

मोदी निर्मित महंगाई से जनता का बुरा हाल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जन विरोधी मोदी सरकार ने इस त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में 22 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की, जिसके चलते ही बाजार में सभी तरह के खाद्य तेलों के दाम लगभग डेढ़ गुना बढ़ गए। क्रूड पॉम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5.5 के स्तर से बढ़कर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है, अर्थात सीधे तौर पर 22 फ़ीसदी की बढ़ोतरी मोदी सरकार के मुनाफाखोरी का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी राज में लगातार रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, यही कारण है कि तमाम खाद्य पदार्थों की कीमतों में इसका असर साफ दिख रहा है। दाल की कीमते दोगुनी हो गई है, लहसुन 400 किलो, आलू, प्याज, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी, घटते इनकम से लोग परेशान हैं वही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में घर का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही महंगाई बेलगाम हो चुकी हैं।

बच्चों की दक्षता जांचने छत्तीसगढ़ के 3420 स्कूलों में होगी परीक्षा, केंद्र सरकार करेगी मानिटरिंग

रायपुर। केंद्र शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय (एनसीईआरटी) द्वारा छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 03 से 09 तक के विद्यार्थियों की दक्षता को जांचने-परखने राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर को किया जाएगा. राज्य शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने हर स्तर पर व्यापक प्रशासनिक, प्रबंधकीय व अकादमिक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी विद्यार्थी पूर्व तैयारी कर स्वयं को भी परख सके. परख-2024 आकलन कार्य सभी जिलों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी बनाया गया है. कुल 99 जिला स्तरीय अधिकारी जिले में परख

क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसी तरह सभी 146 विकासखंडों में बीईओ, बीआरसीसी तथा संकुल प्राचार्य को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत देशभर में एक साथ होने जा रहे इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है. बता दें केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है. इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप कक्षा तीन, छह एवं नौ में आधार भूत प्रारंभिक एवं मध्य चरणों के अंत में छात्रों की दक्षता का आकलन किया जा रहा है. यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ के मात्र छात्रों का नहीं बल्कि, शिक्षक, स्कूल तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का मूल्याँकन सिद्ध होगा, जिसके आधार पर भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता का श्रेणी निर्धारण भी होगा. परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कक्षा 3 के लिए भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया से 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे. कक्षा 6 के लिए उक्त विषयों से संबंधित 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएंगे. कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट पर हल करने होंगे. परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र दिया जाएगा।

भाजपा सरकार शराब की काली कमाई छिपाने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर - कांग्रेस

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार द्वारा शराब परोसने बनाई गई मनपसंद एप का विरोध कर भाजपा को आईना दिखाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिससे शराब के कमीशन के प्रेम में डूबे भाजपा नेता बौखला गये और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे एवं फर्जी आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। विपक्ष का आवाज दबाने भाजपा सरकार लगातार पुलिस तंत्र का उपयोग कर कांग्रेस नेता पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। भाजपा का यह चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। शराबबंदी की बड़ी-बड़ी बात करने वाली भाजपा सरकार में आने के बाद शराब की काली कमाई में लग गई है। विपक्ष में रहकर शराब को लेकर तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा की सरकार प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने की प्रयास में रोज नये प्रयोग कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार से पूछा कि - भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में शराब बंदी कब लागू होगी? शराब पीने के लिये शराब दुकानों के बगल में एयर कूल्ड अहाते क्यों खोले गये? सरकार ने ढाबों एवं रेस्टोरेंट में शराब बिक्री करवाने का निर्णय क्यों लिया? बार में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है, ढाबों एवं रेस्टोरेंट में तो बच्चे भी जाते है क्या सरकार वहां बच्चों को भी शराब परोसेगी? मनपसंद एप सरकार ने क्यों बनाया गया, यह शराब की बिक्री बढ़ाने का तरीका नहीं है? विगत 11 महिनों में 2-2 बार शराब की कीमतें बढ़ाये, 3-3 बार शराब क्रय की नीति बदली फिर भी अवैध बिक्री को संरक्षण देने का कारण क्या है? प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी दुकानों में प्रति पेटी 200 रू. देकर कोचियों शराब क्यों उपलब्ध कराई जा रही है? राज्य में एफ एल 10 का लाइसेंस निरस्त कर सरकार ने शराब दुकानों से सीधे शराब खरीदने का निर्णय क्यों लिया, शराब कंपनियों से मिलने वाला कमीशन कहां जा रहा है?

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.